कमल संदेश

‘लोक-कल्याण संकल्प पत्र’ जारी

वर्ष-12, अंक-04, 16-28 फरवरी, 2017 (पाक्षिक) ₹20

बजट 2017

ग्रामीण भारत
रोजगार में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

कृषि
5 सालों में किसानों की आय दुगुनी

कर प्रशासन
ईमानदारों का सम्मान

कुशल आर्थिक प्रबंधन
संसाधनों का सर्वोत्तम विकास

जन सेवा
बेहतर सेवाएं मुहैय्या

डिजिटल अर्थव्यवस्था
गति, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता

वित्तीय क्षेत्र
उदारीकरण और संस्थाओं की मजबूती

इंफ्रास्ट्रक्चर
उत्पादन व कुशलता

गरीब
जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार

नौजवान
शिक्षा, कौशल और रोजगार मुहैय्या कराना

परिवर्तनकारी, ऊर्जावान व स्वच्छ भारत की ओर

गांवों का विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट | विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक लाभ होंगे | स्वच्छ-स्वस्थ-सर्वत्र

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

फिरोजाबाद (उ.प्र.)

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

हाथरस (उ.प्र.)

पौड़ी (उत्तराखंड)

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइटः www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

09 गांवों का विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने एक फरवरी को संसद में बजट 2017-18 पेश किया। यह बजट कई मामलों में ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व है। बजट में न सिर्फ गांवों के विकास पर ध्यान दिया गया है, बल्कि ग्रामीण...

वैचारिकी

राष्ट्र जीवन की समस्याएं 13

श्रद्धांजलि

रामदास अग्रवाल नहीं रहे 15

लेख

स्वच्छ-स्वस्थ-सर्वत्र
जगत प्रकाश नड्डा 26

शहरी और ग्रामीण एवं गरीब लोगों के बीच अंतर कम करने का प्रयास
डा. आर. बालाशंकर 28

काले धन को समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण आवश्यक
डा. अनिर्बान गांगुली 29

साक्षात्कार

बाबुल सुप्रियो, केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री 19

संसद में चर्चा

राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भाषण 22

एक-एक भारतीय के जीवन से जुड़ा हुआ बजटः प्रभात झा 25

अन्य

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार 31

संगठनात्मक गतिविधियां

06 यूपी के विकास के लिए 'लोक-कल्याण संकल्प पत्र' जारी

भारतीय जनता पार्टी ने 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 के लिए...

33 स्वच्छ और विकासशील प्रशासन भाजपा का लक्ष्यः अरुण जेटली

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 4 फरवरी को उत्तराखंड में आगामी विधानसभा...

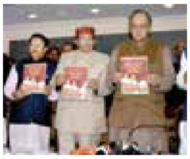

सरकार की उपलब्धियां

16 आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक लाभ होंगे

संसद में 31 जनवरी को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में कहा गया है...

12 उत्तम बजट पेश कियाः नरेंद्र मोदी

आम बजट को देश में बदलावों की दिशा में आगे बढ़ने वाला बजट बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के...

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@JPNadda

स्वस्थ रहना हर बच्चे का हक़ है और उनको कृमि मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी।

@rsprasad

अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार, अपराध और परिवार की हताशा का गठबंधन है।

@byadavbjp

सपा/बसपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में अराजकता और कानूनी अव्यवस्था की स्थिति चरम पर थी। अपराध के मामले में प्रदेश में 61% की वृद्धि हुई है।

@PiyushGoyal

सरकार की नीतियां कतार के अंतिम व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाने के लिये हैं, हम समाज का समग्र विकास चाहते हैं।

facebook

2014 के पहले प्रश्न था - किस स्कैम में कितना गया। आज सवाल है - मोदी जी कितना लाये। ये मेरे लिए ख़ुशी की बात है।

- नरेंद्र मोदी

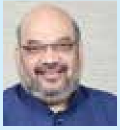

अखिलेश कहते हैं कि काम बोलता है, यूपी में सर्वत्र भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला है, बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बना दिया है।

- अमित शाह

अंत्योदय के कल्याण के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का क्रांतिकारी विचार दुनिया को दिया। वह कहा करते थे कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता हैं, केवल भारत ही नहीं। माता शब्द हटा दीजिये तो भारत केवल जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जायेगा। भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है कि यह जीवन को एक एकीकृत रूप में देखती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों के भारत के निर्माण के लिए हम संकल्पित हैं। अंत्योदय का कल्याण मेरे जीवन का लक्ष्य है।

- शिवराज सिंह चौहान

साभार: जनसत्ता

पाथेय

हमारा यह दृष्टिकोण है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र नहीं है, जिसका जन्म 1947 में हुआ बल्कि यह एक प्राचीन राष्ट्र है। जिसकी परिभाषा इसी अद्वितीय एवं एक सूत्र में पिरोने वाली सांस्कृतिक पहचान द्वारा की गई। यह मार्क्सवादियों के उस भारत से भिन्न है, जो इसे छोटे–छोटे राष्ट्रों का समुच्चय मानते हैं। यह कांग्रेस के उस दृष्टिकोण से भी भिन्न है, जिसके अनुसार भारत का जन्म एक भौगोलिक इकाई के रूप में 1947 में हुआ।

-कुशाभाऊ ठाकरे

परिवर्तनकारी एवं भविष्योन्मुखी बजट

बजट 2017–18 निर्णायक कदम, अभिनव पहल तथा दूरगामी नीतियों के लिए जाना जाएगा। औपनिवेशिक परंपराओं से अलग भारतीय आवश्यकता के अनुरूप उठाए गए कदमों से बजट सही मायनों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। एक महीने पहले बजट प्रस्तुत कर तथा योजना और गैर–योजना वर्गीकरण को हटाकर संसाधनों का अधितम उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। रेल बजट को मुख्य बजट का अंग बनाने से पूरे परिवहन प्रणाली के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का निर्माण होने में सहायता मिलेगी। यह बजट मोदी सरकार की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है, जिसमें परिवर्तनकारी पहलों से भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर ले जाया जा सकेगा। अर्थव्यवस्था को दिशाहीनता, नीतिगत पंगुता, भ्रष्टाचार और बिचौलियों की जकड़ से मुक्त कराकर परिणामकारक, पारदर्शी और गतिशील बनाने का श्रेय कोई भी सहज रूप से मोदी सरकार को देगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा नीत राजग सरकार ने दो–ढाई वर्षों में ही हर ओर व्यापक परिवर्तन किए हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री जब इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करने के लिये खड़े हुए, तब इस वर्ष के 'परिवर्तनकारी, ऊर्जावान एवं स्वच्छ भारत' के एजेंडे से पूरे देश में एक नया उत्साह भर दिया। मोदी सरकार ने सुशासन एवं सरकारी कार्य प्रणाली में अनेक गुणवत्तापूर्ण बदलाव किए हैं। इन सकरात्मक बदलावों से समाज में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है, जिससे कमजोर, वंचित, युवा एवं महिला राष्ट्रीय जीवन में अपना योगदान करने में स्वयं को सक्षम महसूस कर रहे हैं। गरीबों के अधिकारों पर डाका डाल कर फल–फूल रहे भ्रष्टाचार, कालाधन एवं काली अर्थव्यवस्था के विरुद्ध मोदी सरकार ने युद्ध छेड़ रखा है। कांग्रेस की सरपरस्ती में चल रहे इस व्यवस्था से इनमें कई प्रकार के निहित स्वार्थ जड़ जमा चुके हैं तथा इससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। देश के गरीबों को न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार अब इन पर चोट कर रही है।

> इस वर्ष के बजट ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, सीमांत एवं वंचित वर्गों के लिए दूरगामी योजनाओं के माध्यम से भारी राशि की व्यवस्था की है। यह पहली बार है कि मोदी सरकार के हर बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी निवेश किया जा रहा है तथा ग्रामीण भारत केन्द्रीय बजट की मुख्य प्राथमिकता बन चुकी हैं। ग्रामीण भारत की अनदेखी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर हुई है, जिससे कृषि को भारी नुकसान तो हुआ ही साथ में गांवों से पलायन के कारण शहरी जीवन पर भी भारी असर पड़ा है।

इस वर्ष के बजट ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, सीमांत एवं वंचित वर्गों के लिए दूरगामी योजनाओं के माध्यम से भारी राशि की व्यवस्था की है। यह पहली बार है कि मोदी सरकार के हर बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी निवेश किया जा रहा है तथा ग्रामीण भारत केन्द्रीय बजट की मुख्य प्राथमिकता बन चुकी हैं। ग्रामीण भारत की अनदेखी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर हुई है, जिससे कृषि को भारी नुकसान तो हुआ ही साथ में गांवों से पलायन के कारण शहरी जीवन पर भी भारी असर पड़ा है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था दबाव में आ गयी है। इससे देश में भयानक सामाजिक–आर्थिक संकट खड़े हुए हैं। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने, सिंचाई में भारी निवेश, मनरेगा को प्रभावी बना कर और कृषि में व्यापक बीमा तथा अभिनव तकनीकों को प्रोत्साहित कर मोदी सरकार पूर्व की गलतियों को तेजी से सुधारने में लगी हुई है।

सरकार के आलोचक तक अब यह मानने को बाध्य है कि बजट परिवर्तनकारी एवं भविष्योन्मुखी है। भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने में 'परिवर्तनकारी, ऊर्जावान, एवं स्वच्छ भारत' का घोषवाक्य अवश्य सफल होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार में वह दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति है जिससे वह समस्याओं को देखने का नजरिया बदलने का दम रखती है। अब तक की थकी–थकाई मानसिकता, जिसमें भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी तथा काली अर्थव्यवस्था फल–फूल रही थी, के स्थान पर वित्तीय समझ, आर्थिक सजगता एवं परिणामकारी शासन ने ले लिया है। इसका परिणाम यह है कि कांग्रेस नीत यूपीए शासन में जो मुद्रास्फीति दहाई का आंकड़ा पार करती थी, अब निरंतर इस पर लगाम कसी जा चुकी है। विकास दर जो लुढ़क रही थी, अब तेजी से ऊपर उठा है और कालेधन एवं भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा रही है। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकता सितारा बनकर उभरा है तथा सर्वाधिक तेज विकास वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस वर्ष के बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था उन शक्तियों को प्राप्त करेगी, जिससे आने वाले वर्षों में एक बड़ी छलांग लगाने में देश सक्षम होगा। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

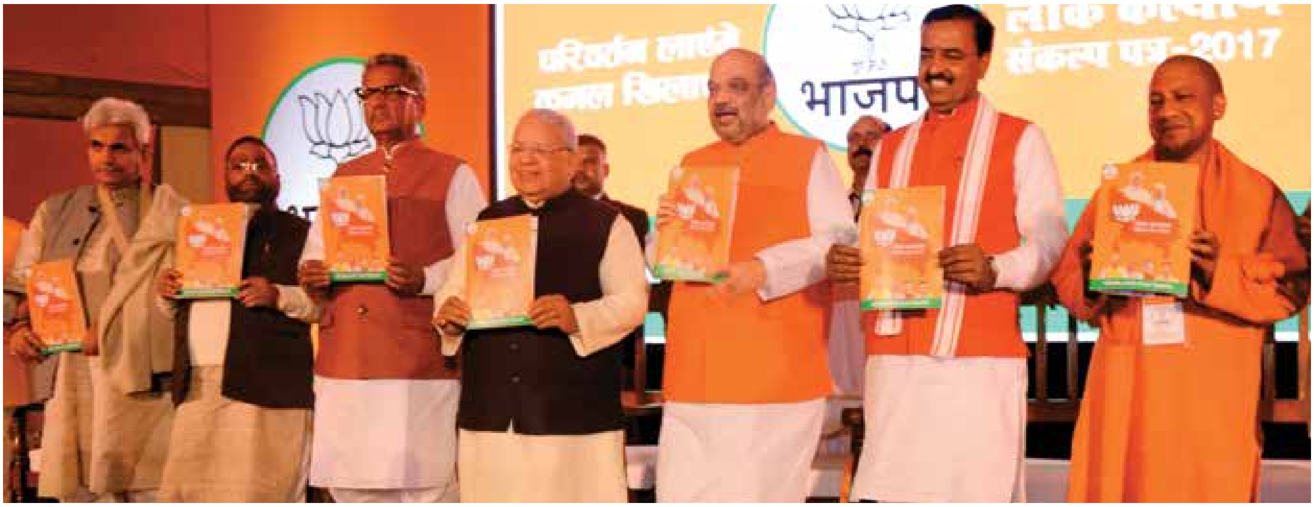

यूपी के विकास के लिए 'लोक-कल्याण संकल्प पत्र' जारी

भारतीय जनता पार्टी ने 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। यह संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश में परिवर्तन, विकास एवं गरीबों के सशक्तिकरण की दिशा में भाजपा के संकल्पों और प्रतिबद्धताओं के संकल्पों का एक ठोस दस्तावेज है।

कृषि विकास का बने आधार

कृषि प्रदेश के विकास का आधार बने इसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। सभी लघु एवं सीमान्त किसानों का फसली ऋण माफ़ किया जाएगा एवं उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर भुगतान की व्यवस्था एवं सरकार बनने के 120 दिनों के भीतर गन्ना किसानों के बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। 2022 तक किसानों की कृषि आमदनी दोगुना करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। गन्ने से इथेनोल एवं ग्लूटेन फ्री आटा आदि बनाने को प्रोत्साहन। भूमिहीन कृषि-मजदूरों के लिए बैंक ऋण, सामाजिक सुरक्षा के लिए जरुरी दस्तावेज, दीन दयाल सुरक्षा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा योजना एवं गौधन योजना के तहत दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदारी की व्यवस्था, सही मूल्य दिलाने के लिए ई-मंडी की व्यवस्था एवं आलू, प्याज एवं लहसून को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी जरूरतमंद को मिले और हर खेत को सही दर पर बिजली मिले, हर ब्लाक स्तर पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज हो। सभी किसानों को एक नया एनर्जी एफिशियेंट पंप मिले, 3 साल में सभी सॉइल हेल्थ कार्ड मिले, फसलों की नील गाय आदि से सुरक्षा हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

हर खेत पानी के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड, बुन्देलखण्ड एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए इसके अतिरिक्त अलग फंड का प्रावधान। केन बेतवा परियोजना शुरू करने पर काम, 50 लाख किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई योजना का लाभ, तालाबों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण आदि को सुनिश्चित किया जाएगा। 150 करोंड़ से डेरी विकास फंड के तहत 5 वर्षों में दुग्ध क्रान्ति की दिशा में काम, 4 जिलों के समूह में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता से 1 संपूर्ण डेरी मिल्क प्रोसेसिंग डेरी की स्थापना की जायेगी। अवैध एवं यांत्रिक कत्लखानों पर कठोरता से प्रतिबन्ध एवं गरीब किसानों के पशुओं के लिए पशु स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जाएगा।

ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार

पुलिस में 1.5 लाख रिक्त पदों को, संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था का सम्मान करते हुए बिना जाति और धर्म के पक्षपात के, सिर्फ मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। विभाग के रिक्त आरक्षित पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा। साम्प्रदायिक तनाव के कारण पलायन रोकने के लिए विशेष विभाग, पुलिस रिकॉर्ड डिजिटाइज, पुलिस बल में एक विशेष कानून और व्यवस्था विंग, पुलिस बल को आधुनिक उपकरण, भयमुक्त FIR की व्यवस्था, 6 फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, अत्याधुनिक ढंग से जेलों को सज्ज करने की व्यवस्था। जेल में बंद गैंगस्टरों एवं पैरोल पर बाहर कैदियों पर सख्ती एवं 15 मिनट में 100 हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। एंटी-भूमाफिया टास्क फ़ोर्स का गठन कर भू-माफियाओं की कब्जे से जमीनों को मुक्त कराया जाएगा। अवैध खनन, भ्रष्टाचार के मामलों में स्पेशल टास्क फ़ोर्स गठित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेड 3 और 4 की भर्तियों से इंटरव्यू समाप्त, भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण

के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में शिकायत करने की व्यवस्था, ई-टेंडरिंग से पारदर्शिता एवं सिटिजन चार्टर से जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। लोकायुक्त क़ानून को मजबूत और प्रभावी बनाया जाएगा।

हर युवा को मिलेगा रोजगार

आगामी पांच वर्षों में 70 लाख रोजगार व स्व-रोजगार के अवसर, प्रदेश की 90 प्रतिशत नौकरियों को प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित, 90 दिनों के भीतर सभी रिक्त पदों पर भर्ती, प्रत्येक घर के एक सदस्य को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। युवाओं के रोजगार एवं स्वावलंबन के लिए 1 हजार करोड़ के स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना एवं प्रदेश में देश का देश का सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा।

प्रत्येक तहसील में आधुनिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना एवं प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज मे दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेद-भाव के मुफ्त लैपटॉप एवं स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के अन्तर्गत प्रति माह 1 GB इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार

सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, सभी लड़कों के लिए कक्षा 12 तक तथा कक्षा 12 में 50% से अधिक पाने वाले लड़कों को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा। गरीब परिवारों से आए छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ के बाबा साहेब अम्बेडकर छात्रवृति कोष की स्थापना एवं कक्षा 12 तक गरीब परिवारों से आये छात्र-छात्राओं को सभी पुस्तकें, स्कूल यूनिफार्म, जूते तथा स्कूल बैग मुफ्त की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 नए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना, हर जिले में एक इंजीनियरिंग अथवा पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में मुफ्त 'वाई-फाई (WiFi)' की सुविधा, सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का आधुनिकीकरण, प्राइवेट स्कूलों की फीस व्यवस्थित करने के लिए एक पैनल, प्रदेश के कॉलेज व विश्वविद्यालय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए विशेष जोर, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की अक्रेडीटेशन (मान्यता) की पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था, प्रत्येक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक एवं एक कक्ष के न्यूनतम अनुपात आदि को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोज़गार समस्या को 3 महीनों में न्यायोचित तरीकों से सुलझाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक नए पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

गरीबी से मुक्ति का सपना साकार

प्रदेश के सभी गरीबों तक बिना जाति और धर्म के भेद-भाव के सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 'गरीब कल्याण कार्ड' का वितरण किया जाएगा, जिसके तहत बी.पी.एल. एवं राशन कार्ड धारकों को सरकारी सुविधाओं का पारदर्शी तरीके से हस्तांतरण हो सकेगा। जनधन एवं आधार योजना की नींव पर बनी यह गरीब कल्याण कार्ड योजना प्रदेश के आर्थिक समावेश एवं सामाजिक उत्थान के लिए काम करेगी।

गरीब कल्याण कार्ड के जरिये सरकारी व पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में सर्जरी, क्रिटिकल केयर सहित सभी प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाएं कैशलेस तरीके से प्राप्त होंगी एवं 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली, पानी और शौचालय के साथ पक्के मकानों के निर्माण के लिए गरीब कल्याण कार्ड के ज़रिये 6 लाख तक का आवास ऋण रियायती दरों पर मिल सकेगा। इसके तहत न्यूनतम दाम पर कार्ड धारकों को राशन में तेल, नमक, दाल, चीनी, गुड़ आदि उपलब्ध

पारदर्शिता एवं भयमुक्त उप्र का निर्माण हमारा लक्ष्य : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अमित शाह ने 28 जनवरी को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी का अगले पांच सालों के लिए यूपी का 'लोक-कल्याण संकल्प पत्र' जारी किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व यूपी प्रभारी श्री ओम माथुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य, केन्द्रीय मंत्री श्री मनोज सिन्हा एवं श्री कलराज मिश्र, योगी आदित्यनाथ, स्वामी प्रसाद मौर्य एवं श्री कौशल किशोर मंच पर मौजूद थे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार हमने यूपी का 'लोक-कल्याण संकल्प पत्र' बनाते वक्त राज्य की आम जनता की आकांक्षाओं को जानना चाहा कि उनकी सरकार से क्या अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के करोड़ों लोगों से जनसंपर्क किया है और लोगों की राय जानी है। आकांक्षा पेटी, यूपी के मन की बात व 5000 से ज्यादा छोटी-बड़ी सभाएं करके लगभग 30 लाख से अधिक लोगों की राय ली है व किसान, मजदूर व बेरोजगार के साथ ही दलित व पिछड़ों की आकांक्षाओं को जाना है। इस आधार पर हमने उत्तर प्रदेश का 'लोक कल्याण संकल्प पत्र' तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हमारा यह 'लोक कल्याण संकल्प पत्र' उत्तर प्रदेश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिम्ब है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के 'अन्त्योदय' एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश से गुंडाराज और भ्रष्टाचार को समाप्त कर के पारदर्शी एवं भयमुक्त यूपी का निर्माण करना है।

कराया जाएगा। हर जिले में आश्रयहीनों के लिए पर्याप्त रैन बसेरों का निर्माण एवं शहरी झुग्गी-झोंपड़ियों के स्थानांतरण एवं पुनर्वास के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई जाएगी। सामान्य वर्ग के गरीबों की आर्थिक प्रगति के लिए सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। सभी असंगठित श्रमिकों (ठेला गाड़ी चालक, दुकानों-होटलों में काम करने वाले, घरों में काम करने वाले महिला-पुरुषों, फुटकर हलवाई के साथ कर्मचारी, साइकिल रिक्शा चालकों, अखबार बांटने वाले श्रमिक, इत्यादि) के लिए 2 लाख तक का सुरक्षा बीमा सरकार द्वारा निःशुल्क करवाया जाएगा।

गांव, कस्बा एवं शहरी विकास

प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली, 2 साल के भीतर मुफ्त बिजली कनेक्शन सभी गरीब परिवारों को, सभी गरीब घरों को बिजली की पहली 100 यूनिट 3 प्रति यूनिट की रियायती दर पर, पाइप कनेक्शन के माध्यम से सभी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना, अगले 5 वर्षों में प्रदेश के सभी घरों में शौचालय बनाने का काम, सभी गरीब घरों को निःशुल्क एल.पी.जी.कनेक्शन एवं प्रदेश के सभी महानगरों में पाइप के माध्यम से पी.एन.जी. रसोई गैस की व्यवस्था की जाएगी।

लखनऊ, नोएडा में मेट्रो सेवा का विस्तार, कानपुर,आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद में मेट्रो सेवा आरंभ करने की दिशा में काम, सभी प्रमुख शहरों में वातानुकूलित बस सेवा शुरू करने का काम। शहरों में रिंग रोड, बाईपास, अंडरपास और फ्लाई-ओवर का निर्माण काम। मुख्य सार्वजनिक स्थानों (जैसे बस स्टैंड इत्यादि) पर मुफ्त 'वाई-फाई (WiFi)' की सुविधा आदि की व्यवस्था की जाएगी। मथुरा,काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले चतुर्भुजी तथा ईस्ट-वेस्ट और नार्थ-साउथ रोड कॉरिडोर का निर्माण कार्य, प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों की बाकी देश से हवाई कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नए एयरपोर्टों का निर्माण, प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों के मुख्य पर्यटन स्थलों (लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिशारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि) को हेलीकाप्टर सेवा के ज़रिये आपस में जोड़ने का कार्य संपन्न किया जाएगा। बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में बुंदेलखंड/पूर्वांचल दो विकास बोर्डों का गठन किया जाएगा।

विकसित उद्योग सुगम व्यापार

प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति, सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग, निवेश की राशि को तीन गुना बढ़ाने के लिए एक विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना, प्रदेश में टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 6 आई.टी.पार्कों की स्थापना, अंग्रेजी दवाओं की आवश्यकता एवं खपत को पूरा करने के लिए फार्मा पार्क की स्थापना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशाल औद्योगिक पार्कों की स्थापना एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के हर जिले के स्थानीय व्यापारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रदेश में व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

सशक्त नारी समान अधिकार

प्रदेश के हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50 हजार का विकास बॉण्ड दिया जाएगा। बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर 3 हजार, कक्षा 8 में पहुँचने पर 5 हजार, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7 हजार और कक्षा 12 में पहुँचने पर 8 हजार दिए जाएंगे। बेटी के 21 वर्ष की होने पर 2 लाख दिए जाएंगे। कन्याओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू होगी और गरीब परिवारों में बेटी के जन्म लेने पर 5001 धनराशि गरीब कल्याण कार्ड के माध्यम से दी जाएगी।

स्वस्थ हो हर घर–परिवार

108 एम्बुलेंस सेवा का विस्तार और सुधार करके कॉल करने के 15 मिनट के भीतर आधुनिक एम्बुलेंस दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जाएगी। हर गाँव में आधुनिक सुविधा से लैस प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केंद्र, हर ब्लॉक में जेनेरिक दवा देने वाले दवाखाने, प्रदेश में 25 नए मेडिकल कॉलेज एवं सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल, प्रदेश के 6 क्षेत्रों में 1 AIIMS स्तर का संस्थान एवं सभी अस्पतालों में प्रसव कक्ष को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। अगले 5 साल में प्रदेश को 'कुपोषण मुक्त' बनाया जाएगा एवं योग, आयुर्वेद, होम्योपथी, नेचुरोपैथी तथा अन्य प्रचलित भारतीय चिकित्सा पद्यतियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारा संकल्प

भाजपा का उन मुद्दों पर स्पष्ट रुख है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े हैं। राम मंदिर पर भाजपा अपना रुख दोहराती है - संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाए। प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज हुए मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए सरकार 25 नई विशेष अदालतों का गठन, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृति की राशि बढ़ाई जाएगी तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय की सीमा में बढ़ोतरी, अनुसूचित जाति वर्ग को उच्च शिक्षा हेतु रियायती ब्याज़ दर पर ऋण की व्यवस्था की जाएगी। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिशारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास कर प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट बनाये जाएंगे, जैसे राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट आदि। पर्यटकों की जानकारी, बुकिंग सहायता आदि के लिए एक समर्पित 24x7 राज्य पर्यटन हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी और सभी तीर्थ स्थलों को 4 लेन राजमार्ग के साथ जोड़ा जाएगा। तीन तलाक के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने रुख पर कायम है। ■

गांवों का विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने एक फरवरी को संसद में बजट 2017-18 पेश किया। यह बजट कई मामलों में ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व है। बजट में न सिर्फ गांवों के विकास पर ध्यान दिया गया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश की समग्र अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इस बजट में वित्तीय घाटा कम कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती तो दी ही गई है, साथ ही विदेशी मुद्रा के भारी निवेश को भी प्रोत्साहित किया गया है।

बजट में जहां एक तरफ आधारभूत संरचनाओं के विकास पर भारी धनराशि खर्च करने की व्यवस्था है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों को रोजगार मुहैया करने वाली 'मनरेगा' योजना पर 48,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। गौरतलब है कि 'मनरेगा'को दिया गया यह धन, अब तक आवंटित की गई सर्वाधिक धनराशि है। यही नहीं, किसी राजनैतिक दल को मात्र 2000 रुपये तक कैश लेने की पाबंदी लगाकर राजनैतिक व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाने की ऐतिहासिक पहल की गई है। यही नहीं, ही केन्द्र सरकार ने देश की कृषि अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए बजट 2017-18 में अनेकों उपाय किए हैं, जैसेकि अधिक कृषि ऋण की व्यवस्था, सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिक आवंटन, फसल बीमा योजना इत्यादि।

खेती–किसानी पर सौगातों की बरसात

सरकार ने बजट 2017-18 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी सहायता देते हुए सरकार ने कुल ग्रामीण आवंटन को बढ़ाकर 1 लाख 87,233 करोड़ रुपये कर दिया है, जो कि गत वर्ष से 24 प्रतिशत अधिक है।

किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के कृषि कर्ज का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को कर्ज में प्राथमिकता दिए जाने का फैसला लिया है।

सरकार ने दृढ़ संकल्प किया है कि वह किसानों की कमाई को आने वाले 5 सालों में दुगुना करेगी। केबिनेट ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत आने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का कार्यकाल 15 साल से बढ़ाकर 20 वर्ष तक कर दिया है।

सरकार सोयल हेल्थ कार्ड मुहैया करवाने सहित कृषि विज्ञान केंद्र में मिनी लैब्स को स्थापित करवाएगी। फसल बीमा योजना को 40 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की ओर से माइक्रो इरिगेशन फंड की स्थापना की जाएगी। इसके लिए कुल 5 हजार करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया गया है। नाबार्ड के अंतर्गत 8 हजार करोड़ रुपए की राशि का डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया जाएगा।

भारत नेट परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन

भारत नेट परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ और 1.5 लाख पंचायतों तक तीव्र गति वाले इंटरनेट को पहुंचाने का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की आधारशिला रखेगा।

इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई.नाम को 250 से बढ़ाकर 585 एपीएमसी तक करना एक और स्वागतयोग्य कदम है। यह किसानों को

अपने उत्पाद को बेचने का अधिक विकल्प प्रदान करेगा।

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 4818 करोड़ का बजट तय किया गया है, ताकि मार्च 2018 तक सभी गावों में बिजली पहुंचाई जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए बजट अनुमान 2016-17 में किए गए 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 2017-18 में 23,000 करोड़ रुपए कर दिया है, ताकि जिससे बेघर लोगों और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए 2019 तक एक करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया जाए।

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में सड़कों का विस्तार किया जा सकेगा। सारे गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार की पहल में यह अहम भूमिका निभाएगा। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में 133 किलोमीटर सड़क का प्रतिदिन निर्माण किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 में यह 73 किलोमीटर प्रतिदिन थी।

मनरेगा को रिकॉर्ड 48 हजार करोड़ रुपये का आवंटन

मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना) के आवंटन में रिकॉर्ड 48,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो अब तक इस योजना के लिए किया गया सबसे अधिक आवंटन है। पिछले बजट में मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया था।

मनरेगा में इस साल भी 5 लाख तालाब का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद ली जाएगी, काम स्पेस टेक्नोलॉजी से जांचा जाएगा। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 55 फीसदी हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में 2014 में 42 फीसदी सुधार हुआ था जो अब बढ़कर 60 फीसदी हो चुका है।

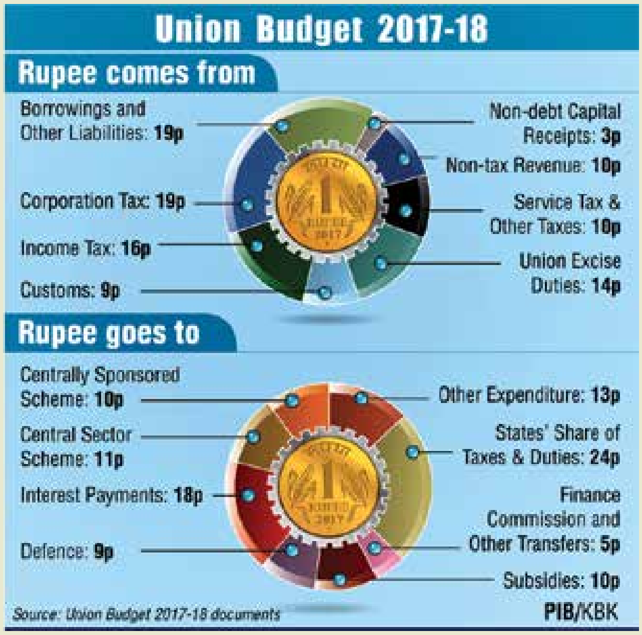

कौशल विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटनों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसके जरिये एक करोड़ गरीब परिवारों को इस बार गरीबी रेखा से बाहर किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और क्रेडिट सहायता योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर तीन गुना से अधिक कर दिया है।

बजट की मुख्य बातें

- 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य
- किसानों को लोन के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रबंध
- नाबार्ड के कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा, ताकि किसानों को कर्ज देने में आसानी हो
- वर्ष 2017-18 में उर्वरक क्षेत्र के लिए दी गई सब्सिडी 70,000 करोड़ रुपए
- फास्फोटिक और पोटाशिक पी एंड के खंड के लिए सब्सिडी को छह प्रतिशत बढ़ाया गया है
- ग्रामीण क्षेत्रों- इन्फ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश
- आधारभूत ढ़ांचे, रोजगार और आवास पर जोर
- किसान कर्ज पर ब्याज में कटौती की गई
- किसानों को कर्ज देने वाली संस्था का कम्प्यूटरीकरण करना
- युवाओं के लिए रोजगार के मौके उपलब्ध कराना
- फसलों के बीमा के लिए किसानों को 9 हजार करोड़
- माइक्रो सिंचाई फंड के लिए 5 हजार करोड़
- डेयरी उद्योग के लिए नाबार्ड के जरिये 8 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम
- मनरेगा के लिए 48000 करोड़ रुपये का बजट (मनरेगा के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रावधान)
- मनरेगा में इस साल 5 लाख तालाब बनाने का लक्ष्य
- एक करोड़ परिवारों के लिए मिशन अंत्योदय
- नार्थ ईस्ट और जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए विशेष मदद
- एक मई 2018 तक 100 फीसदी गांवों का विद्युतीकरण
- कांट्रेक्ट खेती के लिए नया कानून
- ग्रामीण इलाकों में अब 60 फीसदी सैनिटेशन प्रबंध
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़

काले धन पर शिकंजा

मोदी सरकार ने नोटबंदी के निर्णय से ही यह संदेश दिया था कि उसकी मंशा काले धन यानी कि ब्लैक मनी को शिकंजा कसने की है। इसके लिए कड़े निर्णयों के बाद इस वर्ष के बजट में भी यह संदेश दिया है कि ब्लैक मनी पर हर मोर्चे पर शिकंजा कसा जा रहा है। राजनीतिक दल अब नकद में 2000 रुपये से अधिक का चंदा नहीं ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें चेक, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, आरबीआई द्वारा जारी होने जा रहे चुनावी बॉण्ड के जरिये चंदा लेना होगा। तीन लाख रुपये से अधिक राशि की निकासी बंद होगी और इसके लिए अलग से सरचार्ज लगेगा। डाकघरों से पासपोर्ट बनाने के लिए फ्रंट कार्यालय बनाए जाएंगे। जीपीओ से भी पासपोर्ट बनाए जा सकते हैं।

आईआरसीटीसी से रेल टिकट बुक कराने पर अब सेवा शुल्क नहीं देना होगा। रेल सुरक्षा फंड के तहत 5 साल के लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान है। आईआरएफसी, इरकॉन और आईआरसीटीसी की शेयर मार्केट में लिस्टिंग की जाएगी। 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो-टॉयलेट लगेंगे। 3500 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी।

आम लोगों को राहत

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सालाना 3 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को अब आयकर नहीं देना होगा। 3 लाख से 5 लाख रुपये सालाना आय पर 10 प्रतिशत टैक्स के बजाय अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 5 से 10 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

उच्च शिक्षा से जुड़ी सभी जांच परीक्षाएं राष्ट्रीय जांच एजेंसी आयोजित करेगी। आईआईटी जैसी परीक्षाएं अब सीबीएसई नहीं कराएगी। झारखंड और गुजरात में एम्स की स्थापना। ऑनलाइन 350 व्यावसायिक कोर्स कराने की व्यवस्था होगी। अच्छी क्वालिटी के शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे। भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने के लिए ऐसा कानून लाया जाएगा कि विदेश में होने के बावजूद भारत में उनकी संपत्ति जब्त की जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार से जुड़े हेल्थ कार्ड बनेंगे। कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार ने ब्रोकरेज कंपनियों, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर तथा डीमैट अकाउंट में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला किया है।

सस्ते आवास और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणा

वित्त मंत्री ने साल 2016-17 के वर्ष में घोषित 'सस्ते आवास योजना' में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब वर्ष 2017-18 में 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की बजाए अब 30 और 60 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र की गणना की जाएगी। इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ होने के बाद भवन निर्माण को पूरा करने की अवधि को मौजूदा तीन साल से बढ़ाकर 5 साल करने का भी प्रस्ताव किया गया है। सस्ते आवास अब आधारभूत संरचना का हिस्सा होंगे। इससे सस्ते आवास से जुड़ी परियोजनाओं को आधारभूत संरचना से संबद्ध लाभ प्राप्त हो सकेंगे। राष्ट्रीय आवासीय बैंक वर्ष 2017-18 में 20 हजार करोड़ रु. के व्यक्तिगत आवासीय ऋणों का पुनर्वित्त करेगा। विमुद्रीकरण से बैंकों में नकदी का प्रवाह बढ़ा है, जिसके चलते बैंकों ने आवासीय ऋण समेत अन्य ऋणों की ऋण दरें पहले ही कम कर दी हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा आवासीय ऋण पर ब्याज में रियायत की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए आवंटन बढ़ा

बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दे रही है । पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर देते हुए केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आवंटन में 35 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने के साथ अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यकों के आवंटन में भी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।

बजट 2017-18 में अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन 38,833 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपये किया गया है, जो लगभग 35 प्रतिशत अधिक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन बढ़ाकर 31,920 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यक मामलों के लिए आवंटन बढ़ाकर 4,195 करोड़ रुपये किया गया है। सरकार नीति आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में व्यय की परिणाम आधारित निगरानी की शुरुआत करेगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की नई पेंशन योजना घोषित की गई है। इसमें हर साल 8 प्रतिशत का सुनिश्चित रिटर्न मिलेगा। किफायती घरों को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे बिल्डरों को सस्ते मकान बनाने में सरकारी मदद मिल पाएगी और निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा।

लघु एवं मझोले उद्योगों को बढ़ावा

लघु एवं मझोले उद्योग के 50 करोड़ तक के टर्नओवर पर कॉर्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत। इससे 6.67 लाख कंपनियों (96 प्रतिशत) को लाभ होगा। हालांकि, इससे सरकार का राजस्व सालाना 7,200 करोड़ रुपये कम होने का अनुमान है। ■

उत्तम बजट पेश किया: नरेंद्र मोदी

आम बजट को देश में बदलावों की दिशा में आगे बढ़ने वाला बजट बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ-साथ यह पूरी तरह गरीबों के कल्याण पर आधारित है इसलिए यह उत्तम बजट है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 के बजट में किये गये प्रावधानों से ग्रामीणों, किसानों और गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में शिक्षा से व्यवसाय और कपड़ा उत्पादन से लेकर करों में छूट हर क्षेत्र के लोगों के सपने पूरे करने के कदम उठाए गए हैं। बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। मध्यम वर्ग और युवाओं को तो इससे फायदा होगा ही सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का भी लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आवास क्षेत्र को भी बजट से लाभ होगा। बजट में भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करने की प्रतिबद्धता की झलक दिखाई देती है जो नोटबंदी के साथ मिलकर देश में पारदर्शिता लाने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि देश बदलाव के दौर से गुजर रहा है और यह बजट इन बदलावों को लाने में सहायक होगा। श्री

मोदी ने कहा कि इस बार रेल बजट को आम बजट में ही समाहित किया गया है इससे परिवहन क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। रेल सुरक्षा निधि की स्थापना पूंजीगत व्यय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे में ढांचागत क्षेत्र पर जोर दिये जाने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ■

यह बजट गांव, गरीब व किसानों का बजट है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्त्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास के सपने को समर्पित आम बजट, 2017 की सराहना की और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई दी।

बजट की सराहना करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एक ओर तो यह बजट देश के गांव, गरीब और किसानों का बजट है। वहीं दूसरी ओर, यह स्टार्ट-अप के जरिये युवा प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी संभावनाओं को तलाश करने वाला बजट भी है। उन्होंने कहा कि यह बजट इनकम टैक्स में रियायतों के द्वारा मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा फायदा दिलाने वाला बजट है, साथ ही हाउसिंग फंड बढ़ाए जाने से मध्यम व निम्न मध्यम वर्ग के लोगों का अपने घर का सपना साकार हो सकेगा।

श्री शाह ने कहा कि 2014 में हमने राजनीति के अंदर से काले धन के दुष्प्रभाव को नेस्तनाबूद कर पारदर्शिता लाने का जो वादा किया था, उस वादे को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज देश की जनता के सामने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि 70 सालों से देश की राजनीति में काले-धन का जो दुष्प्रभाव रहा, उसने भ्रष्टाचार को

भी बढ़ावा दिया और साथ-ही-साथ हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में कई सारे दूसरे दूषणों को भी पैदा किया। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक दलों के कैश में चंदा लेने की सीमा को 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 करके प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में एक नए युग की शुरुआत की है, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। ■

राष्ट्र जीवन की समस्याएं

भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एकात्ममानव दर्शन के प्रणेता पं.दीनदयाल उपाध्याय कुशल संगठनकर्ता एवं मौलिक विचारक थे। देशभर में उनकी जन्मशताब्दी वर्ष (2016-17) के अवसर पर संगोष्ठियों का आयोजन एवं पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। कमल संदेश में भी हम लगातार उनके द्वारा लिखे गए विचारशील लेखों को प्रस्तुत कर रहे हैं। निम्न लेख 1962 में प्रकाशित पुस्तक 'राष्ट्र चिंतन' से साभार प्रस्तुत है।

| प. दीनदयाल उपाध्याय |

भारत में एक ही संस्कृति रह सकती है; एक से अधिक संस्कृतियों का नारा देश के टुकड़े-टुकड़े करके हमारे जीवन का विनाश कर देगा। अतः आज लीग का द्विसंस्कृतिवाद, कांग्रेस का प्रच्छन्न द्विसंस्कृतिवाद तथा साम्यवादियों का बहुसंस्कृतिवाद नहीं चल सकता। आज तक एक-संस्कृतिवाद को संप्रदायवाद कहकर ठुकराया गया, किंतु अब कांग्रेस के विद्वान भी अपनी गलती समझकर इस एक-संस्कृतिवाद को अपना रहे हैं। इसी भावना और विचार से भारत की एकता तथा अखंडता बनी रह सकती है तथा तभी हम अपनी संपूर्ण समस्याओं को सुलझा सकते हैं।

मनुष्य की अनेक जन्मजात प्रवृत्तियों के समान वह देशभक्ति की भावना को भी स्वभाव से ही प्राप्त करता है। परिस्थितियाँ एवं वातावरण के दबाव से किसी व्यक्ति में यह प्रवृत्ति सुप्त प्रायः होकर विलीन हो जाती है। इस प्रकार विकसित देश प्रेम के व्यक्ति अपने कार्यकलापों की प्रेरणा अस्पष्ट एवं क्षीण भावना से न पाकर अपने स्वप्नों के अनुसार अपने देश का निर्माण करने की प्रबल ध्येयवादिता से पाते हैं। भारत में भी प्रत्येक देशभक्त के सम्मुख इस प्रकार का एक ध्येयपथ है तथा वह समझता है कि अपने पथ पर चलाकर ही वह देश को समुन्नत बना सकेगा। आज यह ध्येयपथ यदि एक ही होता तथा सब देशभक्तों के आदर्श भारत का स्वरूप भी एक ही होता तब तो किसी भी प्रकार के विवाद का संघर्ष का प्रश्न नहीं था। किंतु वस्तुस्थिति यह है कि आज भिन्न-भिन्न मार्गों से लोग देश को आगे ले जाना चाहते हैं तथा प्रत्येक का विश्वास है कि उसी का मार्ग सही मार्ग है। अतः हमको इन मार्गों का विश्लेषण करना होगा और उसी समय हम प्रत्येक की वास्तविकता को भी समझ सकेंगे।

चार प्रमुख मार्ग :

इन मार्गों को देखते हुए हमें चार प्रधान वर्ग दिखाई देते हैं- अर्थवादी, राजनीतिवादी, मतवादी तथा संस्कृतिवादी।

अर्थवादी: पहला वर्ग, अर्थवादी संपत्ति को ही सर्वस्व समझता है तथा उसके स्वामित्व एवं वितरण में ही सब प्रकार की दुरवस्था की जड़ मानकर उसमें सुधार करना ही अपना एकमेव कर्त्तव्य समझता है। उसका एकमेव लक्ष्य 'अर्थ' है। साम्यवादी एवं समाजवादी इस वर्ग के लोग हैं। इनके अनुसार भारत की राजनीति का निर्धारण अर्थनीति के आधार पर होना चाहिए तथा संस्कृति एवं मत को वे गौण समझकर अधिक महत्त्व देने को तैयार नहीं हैं।

राजनीतिवादी: राजनीतिवादी दूसरा वर्ग है। यह जीवन का संपूर्ण महत्त्व राजनीतिक प्रमुख प्राप्त करने में ही समझता है तथा राजनीतिक दृष्टि से ही संस्कृति, मजहब तथा अर्थनीति की व्याख्या करता है। अर्थवादी यदि एकदम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अथवा बिना मुआविजा दिए जमींदारी उन्मूलन चाहता है तो राजनीतिवादी अपने राजनीतिक कारणों से ऐसा करने में असमर्थ है। उसके लिए इस प्रकार संस्कृति एवं मजहब का भी मूल्य अपनी राजनीति के लिए ही है, अन्यथा नहीं। इस वर्ग के अधिकांश लोग कांग्रेस में हैं जो आज भारत की राजनीतिक बागडोर संभाले हुए हैं।

मतवादी: तीसरा वर्ग, मजहबपरस्त या मतवादी है। इसे धर्मनिष्ठ कहना ठीक नहीं होगा; क्योंकि धर्म मजहब या मत से बड़ा तथा विशाल है। यह वर्ग अपने-अपने मजहब के सिद्धांतों के अनुसार ही देश की राजनीति अथवा अर्थनीति को चलाना चाहता है। इस प्रकार का वर्ग मुल्ला-मौलवियों अथवा रूढ़िवादी कट्टरपंथियों के रूप में अब भी थोड़ा बहुत विद्यमान है, यद्यपि आजकल उसका बहुत प्रभाव नहीं रह गया है।

संस्कृतिवादी: चौथा वर्ग है। इसका विश्वास है कि भारत की आत्मा का स्वरूप प्रमुखतया संस्कृति ही है। अतः अपनी संस्कृति की रक्षा एवं विकास ही हमारा कर्त्तव्य होना चाहिए। यदि हमारा सांस्कृतिक ह्रास हो गया तथा हमने पश्चिम के अर्थ प्रधान अथवा भोग प्रधान जीवन को अपना लिया तो हम निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। यह वर्ग भारत में बहुत बड़ा है। इसके लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तथा कुछ अंशों में कांग्रेस में भी हैं। कांग्रेस के ऐसे लोग राजनीति को केवल संस्कृति का पोषकमात्र ही मानते हैं, संस्कृति को निर्णायक नहीं। हिंदीवादी सब लोग इसी वर्ग के हैं।

मार्गों की प्राचीनता :

उपर्युक्त चार वर्गों की विवेचना में यद्यपि हमने आधुनिक शब्दों का प्रयोग किया है। किंतु प्राचीन काल में भी ये चार प्रवृत्तियाँ उपस्थित थीं तथा इनमें से एक प्रवृत्ति को ही अपनाकर हमने अपने जीवन के आदर्श का मानदंड बनाया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही ये चार

प्रवृत्तियाँ हैं। धर्म संस्कृति का, अर्थ नैतिक वैभव का, काम राजनीतिक आकांक्षाओं का तथा मोक्ष पारलौकिक उन्नति का द्योतक था। इनमें से हमने धर्म को ही अपने जीवन का अंग बनाया है क्योंकि उसके द्वारा ही हमने शेष सबको सधते हुए देखा है। इसीलिए जब महाभारत काल में धर्म की अवहेलना होनी प्रारंभ हुई, तब महर्षि व्यास ने कहा...

'ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष न च कश्चिच्छणोति मे।
धर्मादर्धश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते॥'

अर्थ और काम की ही नहीं, मोक्ष की भी प्राप्ति धर्म से होती है; इसलिए धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः।' जिससे ऐहिक संतान एक है और उसको इस एकता का अनुभव करते हुए रहना चाहिए। अनेक अंगों को इकट्ठा करके शरीर की सृष्टि नहीं होती, किंतु शरीर के अनेक अंग होते हैं और इसलिए प्रत्येक अवयव अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए नहीं, अपितु शरीर के अस्तित्व के लिए प्रयत्न करता है। इसी प्रकार राष्ट्र के सभी अंगों को अपनी रूपरेखा राष्ट्रीय स्वरूप और हितों के अनुकूल बनानी चाहिए न कि राष्ट्र को ही इन अंगों के अनुसार काटा-छांटा जाए। संप्रदायों, प्रांतों, भाषाओं और वर्गों का तभी तक मूल्य है जब तक वे राष्ट्र हितों के अनुकूल हैं अन्यथा उनका बलिदान करके भी राष्ट्र की एकता की रक्षा करनी होगी।

प्रथम दृष्टिकोण में अनेक को सत्य मानकर एक की कल्पना का प्रयत्न है तो दूसरे में एक को सत्य मानकर अनेक उसके रूपमात्र हैं जैसे नदी के जल में आवर्त्त – विवर्त्त तरंग आदि अनेक रूप होते हैं किंतु उनका अस्तित्व नदी के जल से भिन्न और स्वतंत्र नहीं और न उनके समुच्चय का ही नाम नदी है। दुःख का विषय है कि आज भी देश की बागडोर, जिनके हाथ में हैं वे प्रथम दृष्टिकोण से ही समस्त समस्याओं को देखते हैं। जब तक राजनीति की इस मौलिक भूल का परिमार्जन नहीं होगा, तब तक राजनीतिक भारत का निर्माण सुदृढ़ नींव पर नहीं हो सकता।

भारत की आत्मा का स्वरूप प्रमुखतया संस्कृति ही है। अतः अपनी संस्कृति की रक्षा एवं विकास ही हमारा कर्त्तव्य होना चाहिए। यदि हमारा सांस्कृतिक ह्रास हो गया तथा हमने पश्चिम के अर्थ प्रधान अथवा भोग प्रधान जीवन को अपना लिया तो हम निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे।

धर्म प्रधान भारतीय जीवन :

भारतीय जीवन को धर्म प्रधान बनाने का प्रमुख कारण यह था कि इसी में जीवन के विकास की सबसे अधिक संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण वाले लोग यद्यपि आर्थिक समानता के पक्षपाती हैं, किंतु वे व्यक्ति की राजनीति एवं आत्मिक सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। राजनीतिवादी प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार देकर उसके राजनीतिक व्यक्तित्व की रक्षा तो अवश्य करते हैं, किंतु आर्थिक एवं आत्मिक दृष्टि से वे भी अधिक विचार नहीं करते। अर्थवादी यदि जीवन को भोग प्रधान बनाते हैं तो राजनीतिवादी उसको अधिकार प्रधान बना देते हैं। मतवादी बहुत कुछ अव्यावहारिक, गतिहीन एवं संकुचित हो जाते हैं। किसी-किसी व्यक्ति विशेष अथवा पुस्तक विशेष के विचारों के वे इतने गुलाम हो जाते हैं कि समय के साथ वे अपने आपको नहीं रख पाते तथा इस प्रकार पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इन सबके विपरीत संस्कृति प्रधान जीवन की यह विशेषता है कि इसमें जीवन के केवल मौलिक तत्त्वों पर तो जोर दिया जाता है पर शेष बाह्य बातों के संबंध में प्रत्येक को स्वतंत्रता रहती है। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रत्येक क्षेत्र में विकास होता है। संस्कृति किसी काल विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के बंधन से जकड़ी हुई नहीं है, अपितु यह तो स्वतंत्र एवं विकासशील जीवन की मौलिक प्रवृत्ति है। इस संस्कृति को ही हमने धर्म कहा है। अतः जब कहा जाता है कि भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है तो इसका अर्थ मजहब, मत या रिलीजन नहीं, किंतु यह संस्कृति ही होता है।

भारत की विश्व को देन :

हमने देखा है कि भारत की आत्मा को समझना है तो उसे राजनीति अथवा अर्थ नीति के चश्मे से न देखकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही देखना होगा। भारतीयता की अभिव्यक्ति राजनीति के द्वारा न होकर उसकी संस्कृति के द्वारा ही होगी। विश्व को भी यदि हम कुछ सिखा सकते हैं तो उसे अपनी सांस्कृतिक सहिष्णुता एवं कर्तव्य प्रधान जीवन की भावना की ही शिक्षा दे सकते हैं, राजनीति अथवा अर्थ नीति की नहीं। उसमें तो शायद हमको उनसे ही उलटे भीख माँगनी पड़े। अर्थ, काम और मोक्ष के विपरीत धर्म की प्रमुख भावना ने भोग के स्थान पर त्याग, अधिकार के स्थान पर कर्त्तव्य तथा संकुचित असहिष्णुता के स्थान पर विशाल सहिष्णुता प्रकट की है। इनके साथ ही हम विश्व में गौरव के साथ खड़े हो सकते हैं।

संघर्ष का आधार :

भारतीय जीवन का प्रमुख तत्त्व उसकी संस्कृति अथवा धर्म होने के कारण उसके इतिहास में भी जो संघर्ष हुए हैं, वे अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए ही हुए हैं। तथा इसी के द्वारा हमने विश्व में ख्याति भी प्राप्त की है। हमने बड़े-बड़े साम्राज्यों के निर्माण को महत्त्व न देकर अपने सांस्कृतिक जीवन को पराभूत नहीं होने दिया। यदि हम अपने मध्ययुग का इतिहास देखें तो हमारा वास्तविक युद्ध अपनी संस्कृति के रक्षार्थ ही हुआ है। उसका राजनीतिक स्वरूप यदि कभी प्रकट भी हुआ तो उस संस्कृति की रक्षा के निमित्त ही। राणाप्रताप तथा राजपूतों का युद्ध केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, किंतु धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही था। छत्रपति शिवाजी ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना गो-ब्राह्मण प्रतिपालन के लिए ही की। सिख-गुरुओं ने अपने युद्ध धर्म की रक्षा के लिए ही किए। इन सबका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि राजनीति का कोई महत्त्व नहीं था तथा राजनीतिक गुलामी हमने सहर्ष स्वीकार कर ली थी। किंतु तात्पर्य यह है कि राजनीति को हमने जीवन का केवल सुख का कारण मात्र माना है, जबकि संस्कृति संपूर्ण जीवन ही है। ■

क्रमशः

रामदास अग्रवाल नहीं रहे

रा जस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के प्रतिष्ठित मंगोड़ीवाले परिवार में जन्मे प्रखर राजनीतिक व समाजसेवी श्री रामदास अग्रवाल 25-26 जनवरी की मध्यरात्रि में पंचतत्व में विलीन हो गए। वे पिछले एक वर्ष से अस्वस्थ थे। श्री रामदास अग्रवाल का जन्म 17 मार्च 1937 को जयपुर में हुआ था। वे श्री रामेश्वर दास अग्रवाल के छः पुत्रों में सबसे बड़े थे। श्री रामदास अग्रवाल के तीन पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। वे मात्र 8 वर्ष की आयु के बाल स्वयंसेवक बने और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे। श्री रामदास दो बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दो बार राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे। साथ ही कई राज्यों में पार्टी के प्रभारी भी रहे। वे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष और आल इंडिया वैश्य फेडरेशन के अध्यक्ष थे।

श्री अग्रवाल पहली बार 1990 में राज्य सभा के सांसद बने। इसके पश्चात् 1996 तथा 2006 में पुनः राज्य सभा के लिए चुने गए। वे 1990 में भाजपा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष बने और अगले 7 वर्षों में भाजपा का अभूतपूर्व विस्तार किया। श्री अग्रवाल 24 दिसम्बर 1999 में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहे। उनकी कार्यशैली और संगठनात्मक सक्रियता के फलस्वरूप 11 जुलाई 2002 और 29 जनवरी 2007 में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल में गए देशभक्तों के परिवारों की हर प्रकार से सहायता की।

उनके निधन पर मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि रामदास अग्रवाल के निधन से भाजपा को क्षति हुई है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यही नहीं, भाजपा के राजनैतिक और रणनीतिकार के रूप में लोकप्रिय श्री अग्रवाल के विपक्षी दलों के साथ भी मधुर संबंध रहे। उनके निधन की जानकारी मिलते ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अशोक परनामी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री सचिन पायलट सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पहुंच कर शोक व्यक्त किया। ■

वे प्रतिबद्ध एवं उत्कृष्ट राजनेता थे

–अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

मुझे जानकार यह अत्यंत दुःख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामदास अग्रवाल जी का निधन हो गया। वे एक समर्पित स्वयंसेवक, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता एवं उत्कृष्ट राजनेता थे।

बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री अग्रवाल 18 वर्षों तक राज्यसभा सांसद तथा दो बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ वे साढ़े सात साल तक राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावे वे दो बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कई राज्यों में पार्टी के प्रभारी भी रहे। वे सामाजिक कार्यों में भी निरंतर सक्रिय रहे और विभिन्न सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे।

सौम्य व्यक्तित्त्व, कुशल सांगठनिक क्षमता, ओजस्वी वक्ता और जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाने वाले एक जुझारू नेता के रूप में श्री रामदास अग्रवाल सदैव याद किये जायेंगे। उनके निधन से देश ने राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन के एक महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ता एवं कुशल मार्गदर्शक को खो दिया है। श्री अग्रवाल का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

दुःख की इस घड़ी में मैं स्वयं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17

विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक लाभ होंगे

संसद में 31 जनवरी को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में कहा गया है कि सुदृढ़ बृहत् आर्थिक स्थिरता की पृष्ठभूमि में पिछले वित्त वर्ष के दौरान दो प्रमुख घरेलू नीतिगत घटनाएं हुईं। प्रथम, संविधान संशोधन पारित होने से ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने का मार्ग प्रशस्त होना और दूसरा, दो बड़े नोटों का विमुद्रीकरण। दरअसल, जीएसटी से एक साझा भारतीय बाज़ार का निर्माण होगा और कर अनुपालन एवं प्रशासन तथा निवेश और आर्थिक वृद्धि में सुधार होगा। जीएसटी भारत के सहकारी संघवाद के प्रबंधन में एक नया ठोस प्रयोग भी है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में कहा गया है कि विमुद्रीकरण की लागत अल्पकालिक है और इससे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे। सरकार ने इन लाभों को अमली जामा पहनाने के लिए अनेक अनुवर्ती उपाय किए हैं, इनमें पुन: मुद्रीकरण, करों में और सुधार आदि शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन उपायों से 2017-18 में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यह भी संभव है कि 2016-17 में आयी अस्थायी कमी के बाद अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से विकास वाली अर्थव्यवस्था हो जायेगी।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 की मुख्य बातें

- वैश्विक स्तर पर सुस्ती छाई रहने के बावजूद भारत अपेक्षाकृत कम महंगाई, राजकोषीय अनुशासन एवं सामान्य चालू खाता घाटे के साथ-साथ आम तौर पर स्थिर रुपया-डॉलर विनिमय दर के वृहद आर्थिक परिदृश्य को बरकरार रखने में सफल रहा है।
- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान स्थिर बाजार मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 में यह दर 7.6 प्रतिशत थी। यह अनुमान मुख्यतः वित्त वर्ष के प्रथम 7-8 महीनों के लिए प्राप्त सूचना के आधार पर लगाया गया है। सरकार का अंतिम उपभोग व्यय चालू वर्ष के दौरान जीडीपी में हुई वृद्धि में मुख्य रूप से सहायक रहा है।

- वित्त वर्ष 2016-17 में नियत निवेश (सकल नियत पूंजी निर्माण) एवं जीडीपी का अनुपात (वर्तमान मूल्यों पर) 26.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 में यह अनुपात 29.3 प्रतिशत था।
- वित्त वर्ष 2017-18 में विकास की रफ्तार सामान्य हो जाने की आशा है, क्योंकि अपेक्षित मात्रा में नये नोट चलन में आ गए हैं, और इसके साथ ही विमुद्रीकरण के बाद आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेज रफ्तार पकड़ कर वर्ष 2017-18 में 6.75 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत के स्तर तक आ जाएगी।

अप्रत्यक्ष करों के संग्रह में बढ़ोत्तरी

- अप्रत्यक्ष करों के संग्रह में अप्रैल–नवम्बर 2016 के दौरान 26.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
- अप्रैल-नवम्बर 2016 के दौरान राजस्व व्यय में हुई खासी वृद्धि मुख्यतः सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल के फलस्वरूप वेतन में हुई 23.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान में की गई 39.5 प्रतिशत की वृद्धि की बदौलत संभव हो पाई।

महंगाई दर नियंत्रण में

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुख्य महंगाई दर लगातार तीसरे वित्त वर्ष के दौरान नियंत्रण में रही। सीपीआई आधारित औसत महंगाई दर वर्ष 2014-15 के 5.9 प्रतिशत से

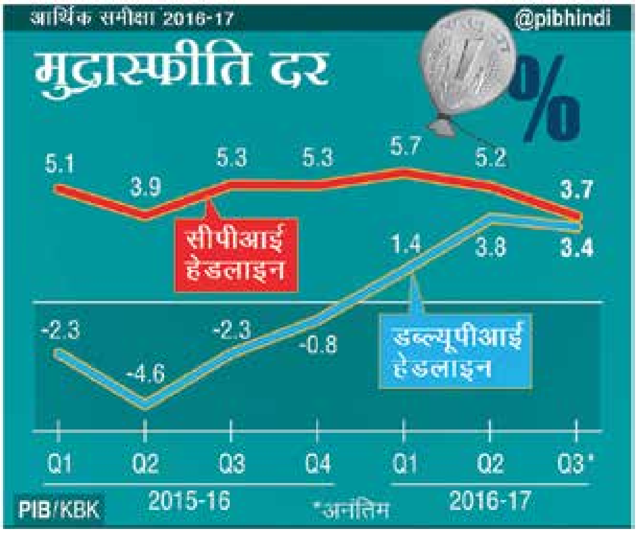

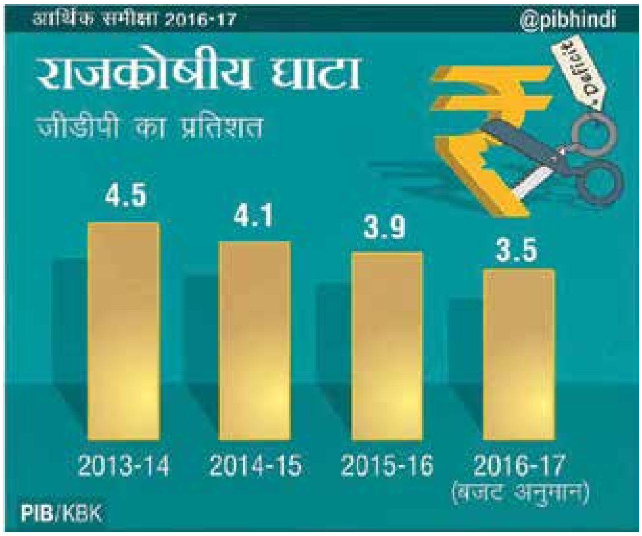

घटकर वित्त वर्ष 2015-16 में 4.9 प्रतिशत के स्तर पर आ गई और अप्रैल-दिसंबर 2015 के दौरान यह 4.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

- थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर वित्त वर्ष 2014-15 के 2.0 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2015-16 में (-)5 प्रतिशत रह गई और यह अप्रैल-दिसंबर 2016 में औसतन 2.9 प्रतिशत आंकी गई।
- महंगाई दर पर बार-बार खाद्य वस्तुओं के संक्षिप्त समूह का ही असर देखा जा रहा है। इन वस्तुओं में से दालों का सर्वाधिक योगदान खाद्य महंगाई में निरंतर देखा जा रहा है।
- सीपीआई आधारित कोर महंगाई दर चालू वित्त वर्ष के दौरान औसतन लगभग 5 प्रतिशत के स्तर पर टिकी हुई है।

व्यापार

- निर्यात में दर्ज की जा रही ऋणात्मक वृद्धि का रुख कुछ हद तक वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) में सुधार के लक्षण दिखाने लगा, क्योंकि निर्यात 0.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 198.8 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान आयात 7.4 प्रतिशत घटकर 275.4 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया।
- वर्ष 2016-17 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान व्यापार घाटा कम होकर 76.5 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 100.1 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया था।
- वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में चालू खाता घाटा (सीएडी) कम होकर जीडीपी के 0.3 प्रतिशत पर आ गया, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 की प्रथम छमाही में यह 1.5 प्रतिशत और 2015-16 के पूरे वित्त वर्ष में यह 1.1 प्रतिशत रहा था।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तेज आवक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की शुद्ध आवक सीएडी के वित्त पोषण के लिहाज से पर्याप्त रहीं, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का रुख रहा।
- वित्त वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बीओपी के आधार पर 15.5 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई।

- वर्ष 2016-17 के दौरान रुपये का प्रदर्शन अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं के मुकाबले बेहतर रहा है।

विदेशी कर्ज

- सितंबर 2016 के आखिर में भारत पर विदेशी कर्ज का बोझ 484.3 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया, जो मार्च 2016 के आखिर में दर्ज किये गये विदेशी कर्ज बोझ के मुकाबले 0.8 अरब अमेरिकी डॉलर कम है।
- सितंबर 2016 में विदेशी कर्ज के ज्यादातर मुख्य संकेतकों ने मार्च 2016 के मुकाबले सुधार का रुख दर्शाया। कुल विदेशी कर्ज में अल्पकालिक ऋणों का हिस्सा सितंबर 2016 के आखिर में कम होकर 16.8 प्रतिशत रह गया और विदेशी मुद्रा भंडार ने कुल विदेशी कर्ज बोझ के 76.8 प्रतिशत को कवर किया।
- कर्ज बोझ से दबे अन्य विकासशील देशों के मुकाबले भारत के मुख्य ऋण संकेतक बेहतर रहे हैं और भारत की गिनती अब भी इस लिहाज से कम असुरक्षित देशों में होती है।

कृषि

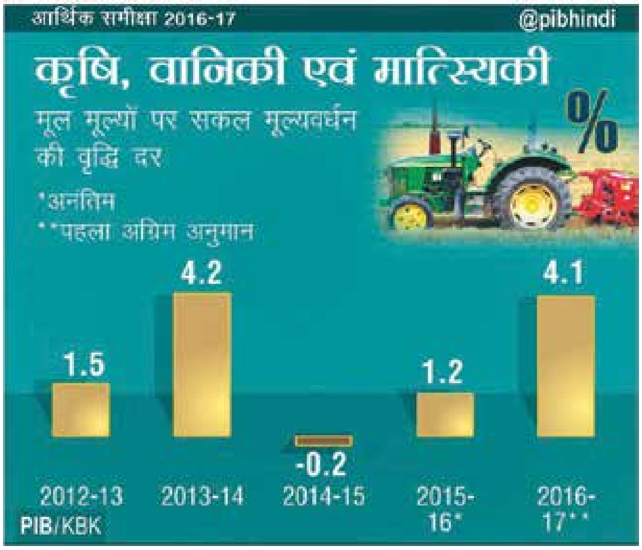

- कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2016-17 में 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 में यह दर 1.2 प्रतिशत रही थी। कृषि क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन को आश्चर्यजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले दो वर्षों के मुकाबले चालू वर्ष में मानसून काफी बढ़िया रहा।
- वर्ष 2016-17 के दौरान 13 जनवरी 2017 को रबी फसलों का कुल बुवाई रकबा 616.2 लाख हेक्टेयर आंका गया, जो पिछले वर्ष के समान सप्ताह में दर्ज किये गये रकबे के मुकाबले 5.9 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2016-17 के दौरान 13 जनवरी 2017 को गेहूं का बुवाई रकबा पिछले वर्ष के समान सप्ताह में दर्ज किये गये रकबे की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक रहा। इसी तरह वर्ष 2016-17 के दौरान 13 जनवरी 2017 को चने का बुवाई रकबा पिछले वर्ष के समान सप्ताह में आंके गए रकबे के मुकाबले 10.6 प्रतिशत ज्यादा रहा।

उद्योग

- आठ प्रमुख ढांचागत सहायक उद्योगों अर्थात् कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली उद्योगों ने अप्रैल-नवम्बर 2016-17 के दौरान 4.9 प्रतिशत की संचयी वृद्धि दर दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह दर 2.5 प्रतिशत थी। अप्रैल-नवम्बर 2016-17 के दौरान रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरकों, इस्पात, बिजली और सीमेंट के उत्पादन में अच्छी-खासी वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन गिर गया। वहीं, कोयले की उत्पादन वृद्धि दर में समान अवधि के दौरान गिरावट का रुख देखा गया।
- कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन (भारतीय रिजर्व बैंक, जनवरी 2017) से यह तथ्य सामने आया है कि वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही के दौरान कुल बिक्री में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही में यह वृद्धि दर महज 0.1 प्रतिशत रही थी। वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही के दौरान इसके शुद्ध मुनाफे में 16.0 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही के दौरान इसमें 11.2 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई थी।

सेवा क्षेत्र

- वर्ष 2016-17 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2015-16 में दर्ज की गई वृद्धि के लगभग बराबर है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कर्मचारियों को मिली अच्छी–खासी धनराशि की बदौलत लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए सेवा क्षेत्र द्वारा तेज रफ्तार पकड़ने का अनुमान लगाया गया है।

सामाजिक बुनियादी ढांचा, रोजगार और मानव विकास

- संसद में 'दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016' पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुरक्षित करने के साथ-साथ इनमें और ज्यादा वृद्धि सुनिश्चित करना है।
- इस अधिनियम में सरकारी प्रतिष्ठानों की रिक्तियों में उन लोगों के लिए आरक्षण स्तर को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें विकलांगता अपेक्षाकृत ज्यादा है और जिन्हें अत्यधिक सहायता की जरूरत पड़ती है। ■

पश्चिम बंगाल को बदहाल स्थिति से मुक्त करेगी भाजपाः बाबुल सुप्रियो

केन्द्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल भाजपा के ऊर्जावान युवा नेता हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बालीवुड में प्लेबैक गायक व अभिनेता के रूप में की। 2014 के लोकसभा चुनाव में श्री सुप्रियो ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा उम्मीदवार के रूप में विजय हासिल की। साथ ही, उन्हें मोदी सरकार में सबसे युवा केन्द्रीय मंत्री बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जुलाई 2016 में सरकार में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री का कार्यभार संभालने से पूर्व उन्होंने राज्यमंत्री के रूप में नगर विकास, आवास और नगरीय गरीबी उन्मूलन की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाई। यही नहीं, स्पष्टवादिता और अभिनव दृष्टिकोण के लिए विख्यात श्री सुप्रियो ने केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ ही पश्चिम बंगाल में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना भी किया।

'कमल संदेश' के एसोसिएट सम्पादक श्री **राम प्रसाद त्रिपाठी** के साथ इंटरव्यू में **श्री बाबुल सुप्रियो** ने बताया कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की हालत निरंतर बद से बदतर होती जा रही है और पूरे राज्य में अस्त-व्यस्तता और लोकतंत्र विरोधी माहौल छाया हुआ है। पश्चिम बंगाल को इस बदहाल स्थिति से मुक्त करने के लिए भाजपा ने संकल्प लिया है। यहां प्रस्तुत है इस साक्षात्कार के प्रमुख अंश:

'प.बंगाल में पिछले 40 वर्षों से भ्रष्टाचार और आतंक का बोलबाला'

एक समय था जब बंगाल देश का सांस्कृतिक और औद्योगिक पावरहाउस हुआ करता था और यह वह प्रदेश था जिसने हमारे समसामयिक समाज के बड़े से बड़े नेताओं को जन्म दिया। यह सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रांति फैलाने के लिए प्रसिद्ध था, जिसने राष्ट्र को प्रेरणा दी। 1940 और 1950 के दशकों में लाखों युवाओं और रोजगार ढूंढ़ने वालों के लिए यह प्रदेश प्रसिद्ध रहा है, परन्तु विगत 40 वर्षों में स्थिति एकदम बदल गई है। आपके विचार में वह क्या कारण है जो बंगाल को विनाश की ओर ले जा रहे है?

दुःख की बात है कि मैं भी इससे सहमत हूं। बंगाल ने हमारे समाज के कुछ बड़े से बड़े मानवों को जन्म दिया। जिनमें से श्री चैतन्य, रामकृष्ण, विवेकानंद, टैगोर, सुभाष बोस, डा. मुकर्जी और अनेक स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक सुधारक रहे हैं। स्वतंत्रता-पूर्व काल में बंगाल स्वतंत्रता अभियान का प्रमुख केन्द्र रहा और यह उद्योग तथा शिक्षा का मुख्य हब माना जाता था, परन्तु जब वामपंथी पार्टियां सत्ता में आई तो राज्य का पतन शुरू हो गया। लोगों द्वारा उनकी जिम्मेदारी का ख्याल न रखते हुए उन्होंने अपना विवेक और समझबूझ खो दी और हिंसा तथा कुशासन का बोझ डाल दिया गया। वामपंथी शासन के लगभग चार दशकों में राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला रहा। विकास कार्यों के बजाए वामपंथी इसे पीछे की तरफ ले गए और पश्चिम बंगाल की रीढ़

की हड्डी ही तोड़ डाली। अपनी नान-परफोर्मेंस और विफलता छिपाने के लिए उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया तथा विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया। साथ ही भय दिखाकर चुनाव जीतने की भी कला सीख ली।

विनाशकारी वामपंथी शासन के बाद सत्ता टीएमसी के हाथों में चली गई। सभी को उम्मीद थी कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की गरिमा फिर से उभर कर आएगी और यह प्रदेश विकसित राज्य बन पाएगा, परन्तु दुर्भाग्य से ममता बनर्जी ने बंगाल को धोखा दिया। केन्द्र सरकार से सहयोग करने की बजाए, जिससे राज्य का तेजी से विकास हो, टीएमसी सरकार ने अपने संकीर्ण राजनैतिक लाभ के लिए टकराववादी रूख अपना लिया। अब, विडम्बना यह है कि टीएमसी सरकार केन्द्र सरकार को जवाब तक नहीं देती है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई बैठक तक में मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं होती है। इनके मंत्री केन्द्रीय बैठको में भाग नहीं लेते हैं। निश्चित ही वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल को तबाह करके रख दिया है और उन्होंने प्रदेश को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वापस लौटना दुश्कर हो गया है, परन्तु ममता बनर्जी की सरकार में राजनैतिक व्यवहार अपने निचले स्तर तक पहुंच गया है।

समग्र विकास की बजाए ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने 'परिवर्तन' का नारा लगाया है, परन्तु राज्य में कहीं भी 'परिवर्तन' नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र तबाह हो गया है, व्यापार ठप हो गया है, उद्योग बंद हो गए हैं, राज्य में काम मिलना बंद हो गया है और अंततः लोगों को राज्य से बाहर जाने पर विवश होना पड़ रहा है। यदि कहीं कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो वह टीएमसी के जीवन स्टाइल में ही दिखाई पड़ता है।

> समग्र विकास की बजाए ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने 'परिवर्तन' का नारा लगाया है, परन्तु राज्य में कहीं भी 'परिवर्तन' नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र तबाह हो गया है, व्यापार ठप हो गया है, उद्योग बंद हो गए हैं, राज्य में काम मिलना बंद हो गया है और अंततः लोगों को राज्य से बाहर जाने पर विवश होना पड़ रहा है। यदि कहीं कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो वह टीएमसी के जीवन स्टाइल में ही दिखाई पड़ता है।

मुख्यमंत्री लोकतंत्र का गला घोंट रही हैं। अब बंगाल अलोकतांत्रिक गतिविधियों का अड्डा प्रसिद्ध हो गया है और राज्य की राजनीतिक संस्कृति का भारी पतन हुआ है। एक बंगाली होने के नाते मुझे इन गतिविधियों पर शर्म महसूस होती है। इस सरकार के नेतृत्व में बंगाल निरंतर विनाश की ओर बढ़ रहा है और उसका पतन शुरू हो गया है।

हाल की घटनाओं को देखते हुए यह बात बहुत साफ है कि टीएमसी कार्यकर्ता विपक्षी नेताओं के घरों, पार्टी कार्यालयों और समर्थकों पर हमला बोल रहे हैं। सरकार प्रायोजित आतंकवाद और गुंडागर्दी से टीएमसी क्या संदेश देना चाहती है।

जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों टीएमसी नेताओं ने कलकत्ता में प्रदेश भाजपा कार्यालय पर हमला बोला । श्रीमती कृष्णा भट्टाचार्य जैसे भाजपा नेताओं के घर जला दिए, जो हावड़ा जिले की धुलागढ़ गांव में, मालदा और अन्य स्थानों पर हिंदुओं के घर जला दिए। लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है।

दूसरे, राज्य में टीएमसी के नेता जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं के लिये जिस भाषा का व्यवहार कर रहे हें, वह सत्ताधारी पार्टी के गरिमा के अनुरूप नहीं है। केन्द्र सरकार के प्रति उनका रवैय्या और कानून-व्यवस्था की स्थिति से पता चलता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी सरकार लोकतांत्रिक मार्ग से विचलित हो चुकी हैं। वह भ्रष्टाचार, अपराध और हुडदंगवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अतः जो कुछ भी बंगाल में घट रहा है, उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के अलावा और किसी पर नहीं जाती है।

तीसरे, ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे तक टीएमसी नेताओं के बीच विपक्षी नेताओं के खिलाफ गंदी से गंदी भाषा में गलियां देने की होड़ लगी हुई है। यहां तक टीएमसी हाई कमान भी उन लोगों को पुरस्कृत कर रहा है, जो अन्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर हमला बोलते रहते हैं। राज्य की पुलिस या तो खामोश रहती है या टीएमसी कार्यकर्ताओं के गुंडाराज का समर्थन करती है। एक तरफ टीएमसी कार्यकर्ता केन्द्रीय मंत्री को भी नहीं छोड़ते, उन पर पत्थरों से हमला बोलते हैं, परन्तु राज्य पुलिस मौन खड़ी रहती है। दूसरी तरफ, पुलिस के बांकुडा सुपरिटेंडेंट, भारती घोष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में उनकी पार्टी का समर्थन करते हुए प्रचार करती हैं। इससे पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस की सांठगांठ की पुष्टि होती है।

टीएमसी ने बंगाल और केरल में वामपंथी शासन की नक़ल की है। अतः इन अपराधिक गतिविधियों के पीछे सत्ताधारी पार्टी का यही उद्देश्य नजर आता है कि वह लोगों के मन में भय पैदा करे और विपक्ष का गला घोंटे।

उत्तरदायी विपक्षी पार्टी के रूप में भाजपा किस प्रकार से हिंसा, अपराध और अव्यवस्था के दूषित चक्र से पश्चिम बंगाल को बाहर लाएगी?

भाजपा का दिनोंदिन उदय हो रहा है और ममता बनर्जी इस संगठन के बढ़ते कदमों को देखकर भयभीत हो रही हैं। यही वजह है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को हमारे छात्र नेताओं तथा राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर हमला बोलने के लिए उकसा रही है। किन्तु, लोकतांत्रिक ढांचे में हिंसा और अपराध का कोई स्थान नहीं होता है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जैसे हमारे नेताओं ने हमेशा रचनात्मक राजनीति पर विश्वास किया है और वे मानते हैं कि विकास से ही सभी समस्याओं

का समाधान निकाला जा सकता है।

हमारे कार्यकर्ता नागरिकों में जागरूकता फैला रहे हैं और टीएमसी प्रायोजित हिंसा और अपराध के खिलाफ राज्य में बंगालियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जल्द ही लोगों में जागरूकता आएगी और ममता बनर्जी की कानूनी अव्यवस्था एवं अलोकतांत्रिक शासन का जनता समुचित उत्तर देगी।

राज्य में ममता बनर्जी के शासनकाल में शारदा से रोजवैली तक बहुत से चिटफंड घोटाले हुए। इन घोटालों में टीएमसी के मंत्री और सांसद शामिल पाए गए और उनमें से कुछ जेल में भी हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

शारदा, रोजवैली और अन्य चिटफंड घोटालों में जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। ये सब वित्तीय अपराध हैं। इसलिए सीबीआई ने समुचित अन्वेषण कर उनमें से कुछ की गिरफ्तार किया है और निश्चित ही उन अपराधियों को दबोचेगी जो कानून के दायरे से बाहर हैं। एक समय था जब ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, परन्तु अब वह भ्रष्ट और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। आने वाले दिनों में टीएमसी बर्बाद हो जाएगी और भाजपा का उदय होगा और राज्य में वह सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरेगी।

मैं राज्य और अपनी पार्टी का उज्ज्वल भविष्य देखता हूं। टीएमसी कीचड़ फैला रही है जिससे बंगाल में 'कमल'का ही उदय होगा। वह दिन दूर नहीं जब भाजपा पश्चिम बंगाल में सता में आयेगी और बंगाल का तीव्र गति से आर्थिक-सामाजिक विकास होगा।

केन्द्रीय मंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल के विकास में आपका क्या विजन है?

एक समय था जब औद्योगिकरण के लिए बंगाल दूसरे राज्यों का नेतृत्व करता था, परन्तु अब वह पीछे की तरफ जा रहा है। कोई भी व्यक्ति पश्चिम बंगाल में निवेश करने के लिए तत्पर नहीं है। पहले ही कई इकाईयां बंद हो चुकी हैं। आए दिन रोजगार के अवसर लुप्त हो रहे हैं। अधिकांश युवा बेरोजगार हैं और कुंठित हैं। किसान और उद्योगपति विवश बने हुए हैं। अतः निराशा के इस वातावरण में संगठन के रूप में भाजपा लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रही है ताकि लोग केन्द्र सरकार की विभिन्न विकास की योजनाओं को समझें और इससे लाभ लें।

हम केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं में विश्वास रखते हैं, जो राज्य का कायापलट कर देंगी और हम युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों का उद्धार चाहते हैं। अतः हमारा मुख्य ध्यान लोगों के विकास पर है।

हाल ही में, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में 'सांसद मेला'आयोजित किया, ताकी केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। लोगों ने इसमें बेहद दिलचस्पी दिखाई है। हम भविष्य में इसे अन्य स्थानों पर भी आयोजित करेंगे। निश्चित ही इससे राज्य को निराशा से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।

पश्चिम बंगाल में भाजपा का क्या भविष्य है?

पश्चिम बंगाल में भाजपा का उज्ज्वल भविष्य है। आम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनका प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हमारे विकास के लिए चौबीसों घंटे काम करते हैं। आज तक ढाई साल के शासनकाल में उनके खिलाफ, उनकी सरकार या उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। सरकार के खिलाफ विपक्ष भी हमला करने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाया है। इसी कारण भाजपा की लोकप्रियता और वोट प्रतिशत दिन-ब-दिन प. बंगाल और देशभर में बढ़ता जा रहा है।

दूसरे, पश्चिम बंगाल में लोग धीरे-धीरे समझने लगे हैं कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जो बिना किसी भेदभाव के विकास ला सकती है। यदि भाजपा सरकार बनाती है तो वह राज्य को विकास मार्ग पर ले जा सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहले ही मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात का विकास कर दिखाया है। और अब वह प्रधानमंत्री के रूप में देश का विकास कर रहे हैं। भाजपा नेतृत्व में चल रही राज्य सरकारों का विकास देश के अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से हो रहा है। हर तरफ भाजपा का मिशन 'विकास' है। वास्तव में हम उदाहरण पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देश के अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास किया जा सकता है।

अंत में, मैं राज्य और अपनी पार्टी का उज्ज्वल भविष्य देखता हूं। टीएमसी कीचड़ फैला रही है जिससे बंगाल में 'कमल'का ही उदय होगा। वह दिन दूर नहीं जब भाजपा पश्चिम बंगाल में सता में आयेगी और बंगाल का तीव्र गति से आर्थिक-सामाजिक विकास होगा। ■

तीरथ सिंह रावत बने भाजपा राष्ट्रीय सचिव

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह ने श्री तीरथ सिंह रावत, विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखण्ड को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया।

एक ताकत के साथ हम दुनिया के सामने प्रस्तुत हों : नरेंद्र मोदी

संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण पर 7 फरवरी 2017 को चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व की जो अवस्था है, उसमें भारत के लिए एक अवसर आया है। एक ताकत के साथ हम दुनिया के सामने प्रस्तुत हों तो मुझे विश्वास है कि हमारे पूर्वज जो सपना देखकर चले थे, उसको हम पूरा कर सकते हैं। हम यहां श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं।

मैं संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने अपने अभिभाषण में जनशक्ति को रेखांकित किया है। हम यह जानते हैं कि कोई भी व्यवस्था, लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक, जनशक्ति का मिजाज कुछ और ही होता है। वर्ष 1975 का कालखंड, जब देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, हिन्दुस्तान को जेलखाना बना दिया गया था, देश के गणमान्य वरिष्ठ नेता जयप्रकाश बाबू समेत लाखों लोगों को जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया था, अखबारों पर ताले लगा दिये गये थे। लेकिन लोकतंत्र को कुचलने के ढेर सारे प्रयासों के बावजूद भी इस देश की जनशक्ति का सामर्थ्य था कि लोकतंत्र पुनः प्रस्थापित हुआ। यह जनशक्ति की ताकत है कि गरीब मां का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। जहां तक स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की बात है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, वर्ष 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देश के कोटि-कोटि लोगों ने जान की बाजी लगाकर लड़ा और सभी ने मिलकर लड़ा था। आज के राजनीतिक वातावरण को हम जानते हैं और पाते हैं कि ज्यादातर राज-व्यवस्थाओं ने, राजनेताओं ने, राज्य सरकारों ने, केन्द्र सरकारों ने जन सामर्थ्य को करीब-करीब पहचानना छोड़ दिया है और यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय भी रहता है। जब हम जनता से कट जाते हैं तो जन-मन से कट जाते हैं। हमने गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए सिर्फ कहा था और इस देश के एक करोड़ बीस लाख से ज्यादा लोग गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए आगे आए। यह सवा सौ करोड़ देशवासियों की शक्ति का परिचय है। राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के माध्यम से मैं इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं और देश के राजनीतिक जीवन में निर्णायक की अवस्था में बैठे हुए निर्णय प्रक्रिया के भागीदार सबका आह्वान करता हूं कि हम हमारे देश की जनशक्ति और उसके सामर्थ्य को पहचानें। हम भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जनआंदोलन की अवधारणा लेते हुए एक सकारात्मक माहौल बनाकर देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके कारण देश की ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। हम देश को उसकी पूर्णता में स्वीकार करें और उसकी जनशक्ति को जोड़ें। इस सरकार ने हर शक्ति को संवारकर जोड़ने और जनशक्ति के भरोसे उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। स्वच्छता के अभियान पर मैं हैरान हूं। इतनी सरकारें आईं और इतने संसद सत्र चले, लेकिन कभी भी संसद में स्वच्छता के विषय पर चर्चा नहीं हुई। यह सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। अतः हमें मिलकर एक स्वर में समाज को इस पवित्र कार्य से जोड़कर गांधी जी के समने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यह तो स्वाभाविक है कि जब राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर चर्चा होती है, तो उसमें बजट की बातें भी आ जाती हैं, लेकिन एक चर्चा आयी है कि बजट जल्दी क्यों लाया गया। यह अंग्रेजी परंपरा से बाहर निकलने की कोशिश के साथ-साथ बजट का उपयोग समय पर किया जाना सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। साथ ही, इसका उद्देश्य दिसम्बर से मार्च तक सरकारी धनराशि के अंधाधुंध खर्च किए जाने की परिपाटी को रोकना भी है। बजट जल्दी लाने के निर्णय पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ही गठित समिति की सिफारिश पर लिया गया है। आप भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन आपने इसको प्राथमिकता नहीं दी। रेलवे के संबंध में हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि 90 साल पहले जब रेल बजट आता था, जब ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रमुख मोड सिर्फ रेलवे ही था, बल्कि अब ट्रांसपोर्टेशन के कई प्रकार के मोड हैं। इसलिए जब तक हम कंप्रिहेंसिवली इस विषय को ट्रांसपोर्ट से जोड़कर नहीं चलेंगे, तो हम समस्याओं से जूझते रहेंगे। इससे रेलवे भी अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में आ जाएगी। इसका न तो निजीकरण किया जा रहा है, न ही इसकी स्वायत्तता से कोई छेड़छाड़ की जा रही है। यह मेरे लिए खुशी की बात है कि मई 2014 से पहले आवाज उठा करती थी कि भ्रष्टाचार में कितना गया, लेकिन आज आवाज आती है कि मोदी जी कितना लाए। इसी प्रकार, वर्ष 1988 में तत्कालीन सरकार ने बेनामी सम्पत्ति का कानून बनाया था। पर क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया। वे कौन लोग थे, जिन्हें कानून बनने के बाद ज्ञान हुआ कि अब कानून दबाने में फायदा है? आपको देश को जवाब देना पड़ेगा और यह सरकार है, जिसने नोटबंदी से पहले पहला कदम उनके खिलाफ उठाया है, कानून बनाया है। मैं आज इस

सदन के माध्यम से भी देशवासियों को कहना चाहता हूं कि मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि एक समान्तर अर्थव्यवस्था डैवलप हुई थी और ऐसा नहीं है यह काम भी आपके संज्ञान में पहले भी आया था। यह विषय आप ही की सरकार की आप ही की कमेटियों ने भी आपको सुझाया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्या कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना है। पर हमें चुनाव की चिंता नहीं है, देश की चिंता है। इसलिए हमने यह निर्णय लिया हैं कुछ लोगों को लगता है कि जब अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही थी, तब आपने ऐसे समय में ऐसा निर्णय क्यों किया? मैं यह कहना चाहूंगा कि डीमोनिटाइज़ेशन के लिए यह समय इतना पर्याप्त था कि देश की अर्थव्यवस्था तंदरुस्त थी। यह तभी सफल हुआ है, जब अर्थव्यवस्था मजबूत थी। दूसरा, ऐसा मत सोचिए कि ऐसा हड़बड़ी में होता है। आप देखिए कि हमारे देश में साल भर में जितना व्यापार होता है, करीब-करीब उतना ही व्यापार दीवाली के दिनों में हो जाता है। यह प्रॉपर टाइम था जब कि सामान्य कारोबार ऊंचाई पर पहुंच गया था, उसके बाद अगर 15-20 दिन दिक्कत होती है और फिर 50 दिन में ठीक-ठाक हो जाएगा। मैं मानता हूं कि इससे जैसे स्वच्छ भारत का मेरा अभियान चल रहा है, वैसे ही आर्थिक जीवन में स्वच्छ भारत का अभियान भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार बेनामी सम्पत्ति का कानून पास हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है। इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है कि मुख्यधारा में आइए, देश के गरीबों का भला करने के लिए आप भी कुछ कन्ट्रिब्यूट कीजिए। एक के बाद एक, विदेश में जमा काले धन के खिलाफ नया कठोर कानून बनाया, प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कही इस बार भी बजट में एक नये कानून की बात कही गयी है, सजा भी 7 साल से 10 साल कर दी है। हमने स्विट्जरलैंड से समझौता किया कि अगर कोई भी हिन्दुस्तानी नागरिक पैसा रखेगा तो वे हमें रियल टाइम इन्फार्मेशन देंगे तो उसका पता चल जायेगा। हमने अमेरिका सहित कई देशों के साथ इस प्रकार के समझौते किए हैं। उसी प्रकार प्रॉपर्टी बिक्री में 20 हजार रुपए से ज्यादा नकद नहीं, इसका फैसला हमने लिया। हमने रियल एस्टेट बिल को पास किया। ज्वैलरी के मार्केट में भी एक प्रतिशत एक्साइज टैक्स डाला, क्योकि चीजों को स्ट्रीमलाइन करना था, किसी को परेशान नहीं करना था। हम 'इन्कम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम' भी लाए। 1100 से ज्यादा पुराने कानून हमने खत्म किए। देश आजाद होने के बाद नौ प्रकार के अलग-अलग नामों से चली हुई योजना चलते-चलते उसे एक नाम दिया गया, जिसे मनरेगा कहते हैं। देश को और आपको खुद को भी जानकर आश्चर्य होगा कि शांत रूप से इतने सालों से चली हुई योजना के बाद भी मनरेगा में 1035 बार परिवर्तन किए गए, पर क्या कारण था कि मनरेगा जैसी योजना जो एक लंबे अर्से से चल रही थी, उसे भी लाने के बाद आपको उसमें 1035 बार परिवर्तन करने पड़े।

सरकार नियमों से चलती है, संवैधानिक जिम्मेदारियों के साथ चलती है। जो नियम आपके लिये थे, वह नियम हमारे लिये भी हैं, लेकिन फर्क कार्य-संस्कृति को भी समझने की जरुरत है। वर्ष 2011 से वर्ष 2014, यानी इन तीन सालों में सिर्फ 59 गांवों में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगा और उसमें भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रावधान नहीं था। प्रोक्योरमेंट भी पूरी तरह से सेन्ट्रलाइज्ड था। अब आप देखिए, हमने पूरी कार्य-संस्कृति कैसे बदली है, एप्रोच कैसे बदली है। हमने प्रोक्योरमेंट को भी डिसेन्ट्रलाइज्ड कर दिया और परिणाम यह आया कि इतने कम समय में अब तक 76 हजार गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ पूरा हो गया। आपकी पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर कहते हैं कि राजीव गांधी कंप्यूटर रिवोल्यूशन लाए, मोबाइल फोन लाए, गांव-गांव कनेक्टिविटी कर दी। जब मैं आज कह रहा हूं कि उस मोबाइल का उपयोग बैंक में भी कनवर्ट किया जा सकता है तो आप कह रहे हैं मोबाइल फोन ही कहां है। यह समझ नहीं आ रहा है मान लीजिए कि फोन चालीस प्रतिशत के पास है तो क्या हम चालीस पर्सेंट लोगों को इस आधुनिक व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में सबका सामूहिक प्रयत्न रहना चाहिए।

डिजिटल करेंसी को हम कम न आंकें। सब्जी और दूध के मोबेलाइजेशन के लिए जितना खर्च होता है, उससे ज्यादा एटीएम मोबेलाइजेशन में खर्च होता है। रोड बनाने का काम टोडरमल और शेरशाह सूरी के जमाने से चल रहा है। पिछली सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रतिदिन 69 किलोमीटर बनती थी, हमारे आने के बाद 111 किलोमीटर बनती है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नॉलॉजी का उपयोग किया। मॉनिटरिंग होती है। हमने रेलवे में ड्रोन का उपोग किया है। काम का हिसाब लेते हैं। ग्रामीण आवास योजना में आपके समय में एक साल में 10,83,000 घर बनते थे, इस सरकार में एक वर्ष में 22,27,000 घर बने। पहले ब्रॉडगेज रेलवे की कमिशनिंग एक साल में 1500 किलोमीटर हुआ करती थी। पिछले साल यह बढ़कर 3000 किलोमीटर यानी डबल हो गई। हम जानते हैं कि राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सभी राज्यों में संकट में हैं। कभी हिन्दुस्तान में लाल किले से एक प्रधान मंत्री द्वारा इसकी चिन्ता की गई थी, इतनी हद तक हालत बिगड़ी हुई। पिछले दो सालों में बिजली उत्पादन में क्षमता बढ़ी। 2014 में सोलर एनर्जी 2700 मेगावाट थी, आज हमने उसे 9,100 मेगावाट तक पहुंचा दिया। उदय योजना के तहत राज्यों को करीब-करीब एक लाख 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बचने वाली है। पहले जहां से कोयला निकलता था, उसके नजदीक नहीं दिया जाता था ताकि रेलवे को थोड़ी कमाई हो जाए। हमारी सरकार ने रैशनलाइज़ कर दिया। उसके कारण कोयले में करीब-करीब 1300 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम हुआ है। आपकी सरकार के समय में एलईडी बल्ब करीब 300 रुपए से 380 रुपए में मिलते थे। एलईडी बल्ब से एनर्जी सेविंग होती है, सरकार ने मिशन के रूप में काम किया। हमने 21 करोड़ एलईडी बल्ब लगाने में सफलता पाई, जिससे 11 हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है। विपक्ष के नेता शिड्यूल्ड कास्ट के बजट को लेकर भाषण कर रहे थे लेकिन बड़ी चतुराईपूर्वक वर्ष 2013-14 के आंकड़े के ऊपर बोलना अच्छा नहीं माना। शिड्यूल्ड कास्ट सब प्लॉन कुल आवंटन वर्ष 2012-13, 37,113 करोड़ रुपए और 2016-17 40,920 करोड़

पिछली सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रतिदिन 69 किलोमीटर बनती थी, हमारे आने के बाद 111 किलोमीटर बनती है।

रुपए यानि 33.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस साल के बजट में 52,393 करोड़ रुपए है। आपको सत्य सुनने की हिम्मत चाहिए। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार है। 17 मंत्रालयों की 84 योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के साथ जोड़ा गया है। 32 करोड़ लोगों को 1,56,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना में दिया गया। इतनी बारीकी से हर जगह पर चोरी और लूट को रोकूंगा तो मेरे ऊपर कितना तूफान आएगा। मैंने गोवा में बोला था कि मैं ऐसे निर्णय करता हूं तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी, मुझे मालूम है। ऐसे बड़े-बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है और ज्यादा होने वाली है। मैंने देश के लिए प्रण किया है इसलिए मैं कदम उठा रहा हूं। हमारे यहां गैस सिलेंडर जाते थे और सब्सिडी मिलती थी जब उसको आधार योजना से जोड़ा तो उसका लिकेजेज करीब 26 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा लिंकेज रुका। जिसकी वजह से हम डेढ़ करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन देने में सफल हुए। राशन कार्ड से आधार को जोड़ने से करीब चार करोड़ यानी 3 करोड़ 95 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए। इससे करीब 14 हजार करोड़ रुपए की रकम, जो बिचैलिए गरीब के हक की खाते थे, गरीबों की तरफ गई। मनरेगा में आधार से पेमेंट दी जाती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि 7,633 करोड़ रुपए का लीकेज बच पाया है और आने वाले वर्षों में भी बचत होगी। मैं कार्य संस्कृति का एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। हर वर्ष राज्यों के मुख्य मंत्री भारत सरकार को इस बात की चिट्ठी लिखते थे कि उन्हें यूरिया मिलना चाहिए। पिछले दो साल से किसी मुख्य मंत्री को यूरिया के लिए चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी, कहीं यूरिया के लिए कतार नहीं लगी है। 5 अक्तूबर, 2007 यूरिया नीम कोटिंग की चर्चा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर द्वारा प्रिंसीपल एप्रूव हुई। आपने कैप 35 परसेंट लगाई। लेकिन जब तक 100 परसेंट नहीं करते हैं तब तक उसका कोई लाभ हीं नहीं होता है। यूरिया चोरी होता है, कारखानों में चला जाता है, किसान के नाम पर सब्सिडी के बिल कटते हैं लेकिन किसान को लाभ नहीं मिलता था। यूरिया का दुरुपयोग सिंथेटिक मिल्क बनाने में होता। इम्पोर्टिड यूरिया को भी नीम कोटिंग कर दिया। आपकी कार्य संस्कृति और हमारी कार्य संस्कृति में फर्क इतना है। इससे धान के उत्पादन में पांच प्रतिशत वृद्धि गन्ने के उत्पादन में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने हम सबसे आह्वान किया है कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव साथ-साथ होने की दिशा में सोचने का समय आ गया है। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अध्यापकों और प्राध्यापकों को चुनाव में काम में जाना पड़ता है। चुनाव के कारण सबसे ज्यादा भविष्य की पीढ़ी को नुकसान हो रहा है। इसके कारण खर्च में भी बहुत बड़ी वृद्धि हो रही है। सिक्योरिटी की ज्यादातर शक्ति चुनावी प्रबंधन में लगाई जाती है। सरकार इसका निर्णय कतई नहीं कर सकती है। अनुभव के आधार पर जिम्मेदार लोगों को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। हमें उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने कृषि सिंचाई योजना पर बल दिया। मनरेगा में कैसा मूलभूत परिवर्तन आया, आपने तीन साल में सिर्फ 600 करोड़ रुपया बढ़ाया था और हमने आकर दो साल में 11000 करोड़ रुपया बढ़ा दिया। हम करीब दस लाख से ज्यादा तालाब बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। इससे हमारे किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना है। मत्स्य पालन के लिए भी छोटे-छोटे तालाब काम में आ सकते हैं। जियो टैगिंग के कारण मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट के अंदर बहुत चीजें होने के बावजूद भी हम उनका उपयोग नहीं कर पाए। फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन फसल बीमा लेने के लिए किसान तैयार नहीं था। इस सदन के सब लोग प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का अध्ययन करें कि हमारे इलाके के किसानों को कैसे मदद मिल सकती है। पहली बार प्राकृतिक आपदा के कारण बुआई न हुई हो, तब भी वह बीमा का हकदार बना है। फसल काटने के बाद भी अगर पन्द्रह दिनों के अंदर कोई और आपदा आयी, तब भी वह फसल बीमा का हकदार बने आप अपने इलाके के किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड के बारे में समझाए। मैं चाहूंगा कि इसमें छोटे-छोटे इंटरप्रिन्योर्स आगे आएं। वे खुद अपनी प्राइवेट लैब बनाएं और खुद सर्टिफाइड लैब के द्वारा धीरे-धीरे गांवों में भी एक नए रोजगार का क्षेत्र भी खुले। यहां पर युवाओं को रोजगार देने के अवसर पर चर्चा हुई। मुद्रा योजना से करीब-करीब दो करोड़ से ज्यादा लोगों को बिना किसी गारंटी के धन दिया गया है। उससे वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ है तथा उसमें एक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने की ताकत आई है।

> **महामहिम राष्ट्रपति जी ने हम सबसे आह्वान किया है कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव साथ-साथ होने की दिशा में सोचने का समय आ गया है।**

हमारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि हर जगह रोजगार की संभावनाएं बढ़ें और सरकार ने उस नीति को अपनाया। हमने स्किल डेवलपमेंट में बल दिया है। प्रधान मंत्री कृषि योजना और प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा योजना से भी नौजवान को रोजगार की संभावना बढ़ेगी। सरकार ने टेक्सटाइल और जूतों के क्षेत्र में अनेक इनीशियेटिव्स लिए हैं, जिसके कारण लोगों को नए रोजगार और नए-नए क्षेत्रों में रोजगार की संभावना हुई है। यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई। सर्जिकल स्ट्राइक के पहले 24 घण्टे में राजनेताओं ने कैसे-कैसे बयान दिए, कैसी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन जब देखा कि देश का मिजाज अलग है तो उनकी अपनी भाषा बदलनी पड़ी। यह बहुत बड़ा निर्णय था और इस निर्णय के बारे में कोई मुझसे पूछता नहीं है। नोटबंदी के बारे में पूछते हैं कि मोदी जी, इसे सीक्रेट क्यों रखा? बोलते हैं कि कैबिनेट को भी नहीं बताया? हम अपने देश की सेना का जितना गुणगान करें, उतना कम है। उसने इतनी सफल सर्जिकल स्ट्राइक की है। हमारी सेना इस राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी सामर्थ्यवान है। हम सभी को अपने देश को आगे बढ़ाना। आज विश्व की जो अवस्था है, उसमें भारत के लिए एक अवसर आया है। एक ताकत के साथ हम दुनिया के सामने प्रस्तुत हों तो मुझे विश्वास है कि हमारे पूर्वज जो सपना देखकर चले थे, उसको हम पूरा कर सकते हैं। मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से अभिनन्दन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। ■

एक-एक भारतीय के जीवन से जुड़ा हुआ बजट: प्रभात झा

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य सभा सांसद श्री प्रभात झा ने 9 फरवरी को राज्यसभा में आम बजट 2017-18 की परिचर्चा में भाग लिया। उन्होंने इस बजट को न केवल गरीबों, किसानों, मजदूरों और दलितों का हितैषी बताया, बल्कि इसे प्रत्येक भारतीय के जीवन से जुड़ा हुआ बजट कहा। हम यहां श्री प्रभात झा के द्वारा दिए गए संबोधन के सारांश को प्रकाशित कर रहे हैं-

2017-18 का यह बजट गरीबों, किसानों, मजदूरों और दलितों के लिए है। इस बजट में भारत के गरीब को केन्द्र बिन्दु बनाया गया है। आपके बजट में कभी किसान नहीं दिखे, आपके बजट में कभी गांव नहीं दिखा। आपने हमेशा वोटरों के लिए बजट प्रस्तुत किये। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नागरिकों के लिए बजट प्रस्तुत किया है।

इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने ग्रामीण आवंटन को बढ़ा कर 1,87,233 करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि 2016-17 के बजट में 87,765 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को कर्ज में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इस साल खेती 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। डेयरी उद्योग के लिए, नाबार्ड के जरिए 8000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। नाबार्ड में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा दिया गया है ताकि किसानों को कर्ज देने में उसे आसानी हो। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अब बढ़कर 60 फीसदी हो चुकी है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 4,818 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, ताकि मार्च, 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा सके। प्रधान मंत्री आवास योजना में ग्रामीणों हेतु आवास के लिए आवंटन को बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि वर्ष 2019 तक एक करोड़ मकानों का निर्माण पूरा करा दिया जाए। ग्रामीण अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वर्ष 2017-18 के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में सड़कों का विस्तार किया जा सकेगा।

इस बार ''मनरेगा'' में 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने पिछले बजट में ''मनरेगा'' के लिए 38,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद ली जाएगी, काम स्पेस टेक्नोलॉजी से जांचा जाएगा। ''मनरेगा'' में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज इसमें 55 फीसदी महिलाएं काम कर रही हैं। दीन दयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के आवंटनों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके जरिये एक करोड़ परिवारों को इस बार गरीबी-रेखा से बाहर किया जाएगा। आप रोजगार के बारे में कह रहे थे। क्या रोजगार सिर्फ नौकरी का नाम है? हम तो ऐसे लोग खड़े कर रहे हैं, जो केवल खुद नहीं कमा रहे हैं, बल्कि वे दूसरे

लोगों को रोजगार देने की चेष्टा की दिशा में बढ़ रहे हैं।

इस बजट में सस्ते आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। वर्ष 2017-18 में 20 हजार करोड़ रुपए के व्यक्तिगत आवासीय ऋण की व्यवस्था की गई है। प्रधान मंत्री द्वारा आवासीय ऋण पर ब्याज में रियायत की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। विमुद्रीकरण की आड़ में राजनीति मत करिए। लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े फैसले किए गए हैं। लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए पचास करोड़ रुपए तक के कारोबार पर निगम कर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे 6.67 लाख कम्पनियां, यानी 96 प्रतिशत को लाभ पहुंचेगा। हमने भारत में हर नागरिक की चिंता की है। गांधी जी के सपनों को साकार किया है। यह बजट एक- एक भारतीय के जीवन के साथ जुड़ा हुआ बजट है।

हमें यह कहा जाता है कि हम अ.जा., अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, किन्तु इस बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आवंटन में 35 फीसदी से अधिक वृद्धि करने की घोषणा की गई है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुसलमानों के लिए आवंटन बढ़ा दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की गई है। किफायती घरों का उल्लेख किया गया है। इस सरकार ने विभिन्न तरीकों द्वारा काले धन पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया है। अब प्रत्येक डाकघर बैंक के रूप में कार्य करेगा। अब चूककर्ता इस देश से भाग नहीं सकते। भगोड़ों की सम्पत्ति को जप्त करने के लिए कानून बनाया जाएगा। मध्यम वर्ग को आयकर में काफी राहत दी गई है। कृषकों और गरीबों का कल्याण इस बजट की मुख्य प्राथमिकता है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि कुछ लोग विमुद्रीकरण के निर्णय से खुश क्यों नहीं है। हमारी सरकार अत्यंत पारदर्शी और ईमानदारी से काम कर रही है। कृपया जनता को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। जनता को इस सरकार पर पूरा विश्वास है। ■

स्वच्छ-स्वस्थ-सर्वत्र

| जगत प्रकाश नड्डा |

अस्वच्छता और पीने योग्य पानी के अभाव का सीधा संबंध रोगों से है किन्तु यह निवारणीय भी है। भारत में सभी उम्र के लोगों में दस्त रोग मृत्यु का पांचवा सबसे बड़े कारक है। पीने के लिए सुरक्षित पानी और अच्छी स्वच्छता पद्धतियों का अभाव आर्थिक उत्पादकता को कम कर देता है और समस्त विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों के 5 प्रतिशत का योगदान करता है, जो केवल अस्वच्छता के कारण प्रत्येक भारतीय के प्रत्येक वर्ष में आठ स्वस्थ दिन कम होने के बराबर है। (स्रोतः फ्यूट्रेल एट आल,2007)। असुरक्षित पानी और अपर्याप्त स्वच्छता अधिकतर गरीबों को प्रभावित करती है। यह रोग भार बार–बार बीमार करते हुए, बच्चों के विकास से समझौता करते हुए अधिकतर बच्चों को भी प्रभावित करता है। यह महिलाओं को भी प्रभावित करता है, जिन्हें लिंग आधारित हिंसा के साथ–साथ सुरक्षित स्वच्छता-सुविधाओं की पहुंच के अभाव के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वस्थ्य परिणामों का सामना करना पड़ता है। यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 564 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं जो भारत की लगभग आधी आबादी के बराबर है। खुले में शौच करनेवालों में दक्षिण एशिया में 90 प्रतिशत लोग और विश्व के 1.1 बिलियन लोगों में 59 प्रतिशत भारत के हैं। मानव स्वास्थ्य और सामान्य हाल–चाल पर असुरक्षित पानी और अपर्याप्त स्वच्छता के कारण प्रतिकूल प्रभावों के लिए अंतरक्षेत्रीय कार्य की जरूरत होती है। बढ़ते रोग भार और भीड़–भाड़ से अस्वच्छता के कारण रोग भार के स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं पर प्रत्यक्ष परिणाम पड़ते हैं। इसके विपरीत सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में खराब गुणवत्ता, स्वच्छता और साफ–सफाई के अभाव के परिणामस्वरूप न केवल खराब स्वास्थ्य परिणाम होते हैं, बल्कि बेहतर गुणवत्ता की धारणाओं के कारण लोग स्वास्थ्य परिचर्या हेतु निजी क्षेत्र को भी चुन लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप जेब से अधिक खर्च करना पड़ता है।

> 'स्वच्छ जल और साफ सफाई– सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना' 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में 25 सितंबर, 2015 को मंजूरी दी गई है।

'स्वच्छ जल और साफ सफाई– सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना'

17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में 25 सितंबर, 2015 को मंजूरी दी गई है। एसडीजी 6 के अंतर्गत लक्ष्यों में से एक यह है कि 'वर्ष 2030 तक महिलाओं और लड़कियों तथा संवेदनशील परिस्थितियों में रहने वालों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी के लिए पर्याप्त और न्यायसंगत स्वच्छता व साफ–सफाई सुलभ्य बनाना और खुले में शौच को समाप्त करना'। यह स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। एसडीजी 6 की उपलब्धि का एसडीएच3 पर आकस्मिक असर पड़ता है जो स्वास्थ्य संबंधित लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ इससे बेहतर समय पर नहीं हो सकता था। दो उप–मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) सहित यह मिशन महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि के रूप में, 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। वर्ष 2015 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में अपने योगदान के रूप में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, केंद्र सरकार के अस्पतालों और राज्यों-संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कायाकल्प पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया। यह समय–समय पर आकलन एवं प्रमाणन के माध्यम से स्वच्छता, सफाई व संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं के उच्च स्तरों को प्रदर्शित करने के लिए देश के जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को बढ़ावा देने व प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखता है। पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने सुरक्षित पेय जल, मानव मल के उचित निपटान, पर्यावरण की स्वच्छता, व्यक्तिगत एवं खाद्य स्वच्छता तथा तरल प्रबंधन व शौचालय के निर्माण एवं व्यावहारिक परिवर्तन ग्राम पंचायतों/शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच करने से मुक्त क्षेत्र बनाने (ओडीएफ) के पक्षों को शामिल करने के लिए अपने सपूंर्ण स्वच्छता अभियान की शुरूआत की है।

अंतर–मंत्रालयी सम्मेलन के मौजूदा प्रयासों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए 29 दिसम्बर, 2016 को पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ-स्वस्थ-सर्वत्र नामक एक संयुक्त पहल की शुरूआत की गयी है। यह पहल सामान्य साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए दोनों मंत्रालयों की कार्यान्वयन रणनीतियों के तालमेल का लाभ उठाने की परिकल्पना करती है। स्वस्थ–स्वच्छ–सर्वत्र के तीन मुख्य घटक हैं – कायाकल्प प्रमाणन प्राप्त करने के लिए ओडीएफ ब्लॉकों में एनएचएम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को सहयोग देना, कायाकल्प पुरस्कार विजेता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की ग्राम पंचायत को खुले में शौच करने से मुक्त बनाने के लिए प्राथमिकता देना तथा सीएचसी/पीएचसी नामितियों को जल स्वच्छता व सफाई संबंधी प्रशिक्षण देना। उन ब्लॉकों को जिन्हें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय व स्थानीय समुदाय के प्रयासों द्वारा खुले में शौच करने से मुक्त बनाया गया है, वहां स्वास्थ्य एवं

'स्वच्छ–स्वस्थ–सर्वत्र' पहल इस अर्थ में अनूठी पहल है कि दोनों मंत्रालय प्रतिरूप रणनीति पर कार्य करेंगे, जिससे प्रत्येक मंत्रालय को उपलब्धियां हासिल करने में सुगमता होगी एवं सुदृढ़ता मिलेगी और पूरकता आएगी जिससे कि पणधारियों को एक साथ कार्य करने व समस्या समाधान का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस पहल में स्वच्छता की कमी व जल जनित रोगों से संबंधी रोग के बोझ को कम करने के द्वारा बेहतर समुदाय व्यवहार व स्वच्छ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र को एक दूसरे का पूरक बनाने की परिकल्पना की गई है।

परिवार कल्याण मंत्रालय अपने सीएचसी को कायाकल्प आकलन के तहत सुविधा केंद्र द्वारा उच्च गुणवत्ता स्वच्छता, सफाई व संक्रमण नियंत्रण के बेंचमार्कों को निम्नतम 70 अंकों के साथ प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख रू. का अनुदान प्रदान करेगा। इसके साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय कायाकल्प पुरस्कार विजेता सुविधा केन्द्र के रूप में मूल्यांकित किए गए पीएचसी की ग्राम पंचायत के ओडीएफ कार्यकलापों को शुरू करेगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय उप सीएचसी व पीएचसी के नामितियों को वॉश प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। पहले चरण में वर्ष 2017–18 के दौरान, ओडीएफ घोषित 700 ब्लॉकों में स्थित सीएचसी तथा वे ग्राम पंचायत/नगर पंचायत जिनमें कायाकल्प पुरस्कार विजेता पीएचसी हैं (प्रति जिला एक–एक) स्थित उन्हें इस पहल में कवर किया जाएगा। परिकल्पित कार्यकलापों का वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रमाणन प्रक्रिया के साथ समापन किया जाएगा। ऐसे सीएचसी व पीएचसी का स्वच्छ रत्न सीएचसी और स्वच्छ रत्न पीएचसी के रूप में नामित किया जाएगा। तदनुसार, अतिरिक्त ब्लॉकों व सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में स्किम का उत्तरोत्तर विस्तार किया जाएगा।

'स्वच्छ–स्वस्थ–सर्वत्र' पहल इस अर्थ में अनूठी पहल है कि दोनों मंत्रालय प्रतिरूप रणनीति पर कार्य करेंगे, जिससे प्रत्येक मंत्रालय को उपलब्धियां हासिल करने में सुगमता होगी एवं सुदृढ़ता मिलेगी और पूरकता आएगी जिससे कि पणधारियों को एक साथ कार्य करने व समस्या समाधान का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस पहल में स्वच्छता की कमी व जल जनित रोगों से संबंधी रोग के बोझ को कम करने के द्वारा बेहतर समुदाय व्यवहार व स्वच्छ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र को एक दूसरे का पूरक बनाने की परिकल्पना की गई है। ■

(लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं।)

बजट 2017 ने लाखों सपनों के पंख लगाए

शहरी और ग्रामीण एवं गरीब लोगों के बीच अंतर कम करने का प्रयास

| डा. आर. बालाशंकर |

कहा गया है कि हमारा यह स्वप्निल बजट दूरदर्शी, निर्णायक एवं साहसी है। विगत में वार्षिक बजटों के बारे में इस प्रकार के उल्लेख किए जा चुके हैं। उदारीकरण में यह शब्द विश्व आर्थिक निर्माण को प्रस्तुत करते हैं, जो नए-राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद के चलते विगत-ट्रंप युग में प्रमुख शब्द बनकर रह गए थे। 8 नवम्बर के महत्वपूर्ण विमुद्रीकरण ने अनिश्चितता, आशा और उम्मीदों का तत्व पैदा कर दिया था तथा साथ ही विपक्ष ने इसे स्थगित करने का जोरदार हंगामा करते हुए कहा था कि इससे जल्द ही पांच राज्यों में होने जा रहे चुनावों पर मतदाता प्रभावित होंगे। विपक्ष को भय रहा है कि बजट लोकलुभावनकारी होगा और इससे एनडीए के पक्ष में मतदाता आकर्षित होंगे। पी. चिदम्बरम जैसे पूर्व वित्त मंत्री का कहना है कि बजट ''आंकड़ों की कार्यकुशलता'' के अलावा और कुछ नहीं है। अरुण जेटली के बजट का विशेष महत्व यही है कि उन्होंने बजट प्रक्रिया की विश्वसनीयता को फिर से बहाल किया है।

बजट के पीछे एक दर्शन छिपा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे बड़े शायराना ढंग से पेश किया है। उन्होंने कहा है कि ''यह बजट हमारे स्वप्नों को दर्शाता है। यह भविष्य का बजट है। इससे भारत की शक्ल ही बदल जाएगी।'' हां, इस सरकार का मुख्य सिद्धांत यही है कि हम भारत का पुनर्निर्माण करें जिससे हर आंख का आंसू पोंछा जाए और पूरी तरह से गरीबी समाप्त हो।

यह बजट प्रधानमंत्री के लाखों स्वप्नों को साकार करने वाला बजट है और अरुण जेटली का यह बजट सराहनीय है। उन्होंने यह बजट ईंट-दर-ईंट, एक के बाद एक बजट प्रस्तुत कर आर्थिक दृष्टि को प्रस्तुत किया है जिससे अंत्योदय विचारधारा सामने आ सके।

2017 का बजट उस विचार की परिणति है जिससे अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर समाप्त हो सके और शहरी तथा ग्रामीण भारत के बीच का अंतर भी समाप्त हो सके।

पिछले चार बजटों में नरेन्द्र मोदी सरकार ने विनिवेश, पर्यावरण, मुद्रास्फीति नियंत्रण, वित्तीय घाटे को कम कर, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और विगत मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके तीव्र विकास पर कहीं अधिक जोर दिया है। जब अगले एक वर्ष नए बजट में 1.5 लाख से अधिक गांवों में डिजीटल कनेक्टिविटी की बात की जाती है तो इसका मतलब गांवों में शहरी सुविधाएं देने का होता है। विशेष आकर्षण की बात यह है कि कभी भी हमारे इतिहास में कृषि के आवंटन को दुगुना नहीं किया गया था। यही बात रेल और सड़क निर्माण के आवंटन पर भी लागू होती है। बजट में सन् 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की बात कही गई है और इसके लिए प्रावधान किए गए हैं।

बजट में गरीबों के लिए एक करोड़ घर बनाने का प्रावधान किया गया है। निर्माण क्षेत्र को भी बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वह मनरेगा योजना के लिए 48000 करोड़ से अधिक का सर्वाधिक आवंटन कर रहे हैं।

सरकार के सामने नए कामों का निर्माण सर्वाधिक तात्कालिक प्राथमिकता रखी गई है। वित्तमंत्री ने यह बात ठीक ही कही है कि वह सार्वजनिक निवेश के जरिए इसकी योजना तैयार कर रहे हैं। स्किल योजना की कई योजनाएं है और इसके लिए बड़ा आवंटन किया है तथा भारतीय युवाओं के लिए रोजगार को मजबूत किया जा रहा है। बजट में बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्किल विकास का वायदा किया गया था, जिससे इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। जैसाकि जेटली ने कहा है कि जब सड़कों का निर्माण होता है तो रेलवे का विस्तार भी होता है और नया स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है और ग्रामीण जॉब गारण्टी पर कहीं अधिक धन खर्च किया जाता है तथा इससे खेतिहर सेक्टर में और अधिक जॉब उपलब्ध होते हैं। बजट में विशेष रूप से सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की बात कही गई है। उतनी ही सराहनीय योजनाएं महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में भी है, जिनके लिए विशेष लक्ष्य रखे गए हैं। गुजरात और झारखण्ड में दो नए AIIMS की मांग की गई जिनसे अन्य राज्यों में इसी प्रकार के विशिष्ट स्वास्थ्य केन्द्र की बात भी कही गई है।

बजट में पर्यटन के प्रमुख विकास चालक और जॉब को कई गुना बढ़ाने की बात कही गई है। इस दिशा में 25 नगरों के आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण तथा 300 आधुनिक स्टेशन तथा परिवहन सुविधाओं

(शेष पृष्ठ 30 पर)

मोदी सरकार ने सब्सिडी बोझ को कम किया है और तीन प्रतिशत की सर्वाधिक मुद्रास्फीति कम की है, जिससे कई वर्षों बाद वास्तविक खाद्य पदार्थों की कीमतें नीचे आई हैं। इससे न केवल योजनाओं के बेहतर ढंग से पर्यावरण पैदा होगा, बल्कि इसने स्वदेशी और राष्ट्रीयता को भी जन्म दिया है।

काले धन को समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण आवश्यक

विमुद्रीकरण के कारण काले धन और आतंकवादी फंडिंग पर गहरी चोट लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी की फंडिंग पर राष्ट्रीय बहस करने की जरूरत पर जोर दिया। यह बात उन्होंने लोकसभा में साहसी कदम उठाते हुए कहा क्योंकि उन्होंने चुनाव परिणामों की परवाह नहीं की बल्कि उन्होंने व्यवस्था में शुचिता और साफ-सुथरेपन की चिंता की।

| डा. अनिर्बान गांगुली |

अनेक आकर्षक विषयों में बजट 2017 ने देश के चुनाव तथा पार्टी फंडिंग को विशेष रूप में सामने रखा। स्वाभाविक है जिन लोगों ने अन्यथा देखने या सोचने में अपनी दिलचस्पी रखी उन्होंने राजनीतिक फंडिंग पर पुनः खामोशी बनाए रखी या पूरी बहस पर पर्दा डाल रखा।

भाजपा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के समक्ष चुनाव फंडिंग व चुनाव में कालेधन की समस्या सदैव एक प्रमुख मुद्दा रहा है। साथ-साथ चुनाव पर बहस कराने कालेधन को समाप्त करने के लिए विमुद्रीकरण की दिशा में चलने और हमारे चुनाव पर इसके प्रभाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के तत्त्वावधान में भाजपा ने इस विषय पर सार्वजनिक रूप से बड़ी बहस कराने की बात कही है। वास्तव में, भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने दिसम्बर में एक टेलीविजन चर्चा के दौरान साफतौर से चुनावों पर कालेधन के प्रभाव को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया था और बताया था कि भाजपा जनसंघ के समय से ही इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रही है।

अपने चुनाव अभियान के दौरान सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव ही राजनीतिक और चुनाव फंडिंग पर व्यवस्था को साफ रखने पर जोर दिया है, जबकि भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने निरंतर और सार्वजनिक रूप से व्यवस्था को साफ रखने पर जोर दिया है। विडम्बना है कि अधिकांश राजनीतिक पार्टियां इस विषय पर खामोश रही हैं, जिनमें विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हैं जो सदैव सार्वजनिक जीवन में शुचिता का बहाना बनाती रही है। विचित्र बात यह भी है कि कांग्रेस सहित ये पार्टियां विमुद्रीकरण के खिलाफ जोरदार आवाज उठाती हैं, जबकि वे इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि इस प्रक्रिया से नकली करेंसी रेकेटियरिंग, कालेधन, आतंकवादी फंडिंग, मानव ट्रेफिकिंग द्वारा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है। क्या ये राजनीतिक पार्टियां उस समय भारतीय संप्रभुत्व और सुरक्षा से वास्तव में कोई संबंध नहीं था और क्या वे अपनी बात बढ़ा-चढ़ा कर कह रहे थे, यह प्रश्न विशेष रूप से हमारे सामने आता है।

अपने चुनाव अभियान के दौरान सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव ही राजनीतिक और चुनाव फंडिंग पर व्यवस्था को साफ रखने पर जोर दिया है, जबकि भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने निरंतर और सार्वजनिक रूप से व्यवस्था को साफ रखने पर जोर दिया है। विडम्बना है कि अधिकांश राजनीतिक पार्टियां इस विषय पर खामोश रही हैं, जिनमें विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हैं जो सदैव सार्वजनिक जीवन में शुचिता का बहाना बनाती रही है।

बहुत पहले 1961 में, जब चुनाव में बड़ा खर्च करने पर पहले ही प्रश्न खड़ा हो गया था, उस समय कांग्रेस पार्टी की फिजुलखर्ची का भंडाफोड़ हो गया था जिस पर पं. दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि किस प्रकार से यह पूरी चुनाव प्रक्रिया और सुशासन को हानिप्रद बना दिया है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इसमें सुधार करने के लिए उपाय नहीं किए गए तो देश के विधानमंडलों में शक्तिशाली लॉबी उभरकर आएगी और यह बात शायद ही उद्देश्यपूर्ण ढंग से सामने आए कि राष्ट्रीय हित में केवल लोगों के कल्याण को ही आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो पार्टियां प्रमुख पार्टियों के रूप में विकसित होना चाहती है उन्हें जल्द लाभ प्राप्त करने के सिद्धांत का त्याग करना पड़ेगा। किन्तु, पिछले कई वर्षों से जल्द लाभ प्राप्त करने के सिद्धांत की कला में कांग्रेस पार्टी ने महारत हासिल की थी और 1967 तक, जब वह पूरे देश में एक प्रमुख पार्टी रही तो उसने पूरी व्यवस्था को अपूर्त

रूप से भ्रष्ट कर दिया।

अवसरवाद और संस्थाओं को मिटाने की जड़ में इसका हित इतना गहन था कि उसमें कोई प्रमुख सुधार या बदलाव की गुंजाइश ही नहीं रहीं- ऐसा कैसे हुआ, आखिर यही वह पार्टी थी जिसने भ्रष्ट मैकेनिज्म और प्रक्रिया से हमारे राज्य संस्थानों को खत्म कर दिया। इस पार्टी की प्राथमिकता किसी भी तरह से चुनाव जीतने और सत्ता में आने की रही। इसने ऐसा कोई प्रमुख कदम उठाने से गुरेज किया जिससे व्यवस्था साफ सुथरी बने, नया जोश और पारदर्शिता आए और सार्वजनिक जीवन और कार्यकलाप में शुचिता सुनिश्चित हो सके। दशकों से बेनामी सम्पत्तियों के खिलाफ रूकावट बनी रही जबकि कालेधन और करों के अनुपालन न होने की स्थिति को बर्दाश्त करना पड़ा। इस सभी से एक छोटे राजनीतिक तबके को लाभ पहुंचा, जबकि मेहनत करने वाले भारतीयों को नुकसान पहुंचा और उन्हें हाशिए का सामना करना पड़ा।

इस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि अत्यंत स्पष्ट रही। यह इसलिए स्पष्ट रही कि विमुद्रीकरण के कारण काले धन और आतंकवादी फंडिंग पर गहरी चोट लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी की फंडिंग पर राष्ट्रीय बहस करने की जरूरत पर जोर दिया। यह बात उन्होंने लोकसभा में साहसी कदम उठाते हुए कहा क्योंकि उन्होंने चुनाव परिणामों की परवाह नहीं की बल्कि उन्होंने व्यवस्था में शुचिता और साफ-सुथरेपन की चिंता की।

प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि अत्यंत कड़ी रही। यह इसलिए कड़ी रही कि विमुद्रीकरण के कारण काले धन और आतंकवादी फंडिंग पर गहरी चोट लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी की फंडिंग पर राष्ट्रीय बहस करने की जरूरत पर जोर दिया।

इन उपायों से जनशक्ति को बहुत लाभ पहुंचा और यह जनशक्ति ही है जो इस व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने के लिए हर प्रयास का अन्ततः समर्थन करती है। जैसा कि दीनदयाल जी ने लिखा था- ''जो राजनीतिक दल लोगों के लिए खड़े होते हैं, वे लोगों की शक्ति के लिए भी खड़े होते हैं।'' पिछले लगभग तीन महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने साफतौर पर बता दिया कि 'जनशक्ति पर' ही दृष्टि से उनका क्या मतलब है।'' ■

(लेखक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी रिसर्च फाउण्डेशन, नई दिल्ली के निदेशक तथा भाजपा पुस्तकालय और डाक्युमेंटेशन विभाग के सह-संयोजक हैं।)

(पृष्ठ १८ का शेष)

को बढ़ा कर पर्यटन स्थलों का महत्वपूर्ण उपाए किए गए हैं।

हालांकि विमुद्रीकरण से सरकार के खजाने में भरमार हुई है, परन्तु पिछली यूपीए सरकार की तरह से मोदी सरकार ने फिजुलखर्ची नहीं की है। एनडीए विकास मिशन के प्रमुख क्षेत्र वित्तीय अनुशासन तथा घाटे पर रोक लगाना प्रमुख क्षेत्र में आता है। इस रवैये को देखते हुए मोदी सरकार ने सब्सिडी बोझ को कम किया है और तीन प्रतिशत की सर्वाधिक मुद्रास्फीति कम की है, जिससे कई वर्षों बाद वास्तविक खाद्य पदार्थों की कीमतें नीचे आई हैं। 2017 का बजट कई मायनों में अद्वितीय है। इससे न केवल योजनाओं के बेहतर ढंग से पर्यावरण पैदा होगा, बल्कि इसने स्वदेशी ओर राष्ट्रीयता को भी जन्म दिया है। रेलवे बजट को शामिल करने से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की योजनाएं और अधिक कारगर साबित होंगी।

इस तथ्य को देखते हुए कि वेतनभोगी ग्रुप आय प्रदाता समुदाय है, इसलिए इनके लिए अधिक रियायत की उम्मीद थी ताकि इन्हें उनकी ईमानदारी और इंसेंटिव अनुपालन का पुरस्कार मिल सकें। इन्हें जो भी राहत मिलती है, उससे बहुत हद तक पार्टी के नगरीय वोटों की सद्भावना की रक्षा हो सकेगी। एक और क्षेत्र भी है, जहां वित्त मंत्री ने एसएमई की कर रियायत में उदारता बरती है। इससे विनिर्माण हब जैसी भारत की स्थिति और अधिक बढ़ जाएगी। मुद्रा ऋणों में दुगुने आवंटन किए जाने से इस क्षेत्र में और अधिक इंसेटिव का निर्माण होगा।

ऋण न चुकानें वालों की संपत्ति जब्त करने का निर्णय भी उतना ही सराहनीय है, जैसा कि हमने देखा है कि विजय माल्या जैसे लोग देश से बाहर फरार हो गए थे। सरकार अभी तक एनपीए जैसे मामले पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, जो यूपीए के दस वर्षों के शासन में जमा होता रहा है। एनपीए कुशासन के अनुसार वर्तमान और बट्टे खाते की राशि 15 लाख करोड़ से भी कहीं अधिक है। यह बहुत बड़ा भारी 'स्कैम' रहा है। राजनीतिक संरक्षण के कारण प्रायः अपराधी बेबाक छूट जाते थे।

इस संदर्भ में सरकार के राजनीतिक धन से छुटकारा देने के साहसिक निर्णय की सराहना की जानी चाहिए। यह क्षेत्र कालेधन का सर्वाधिक क्षेत्र रहा है। कालेधन को श्वेत करने का एक उपाए न्यासों को धन और डोनेशन कम करने का निर्णय है। यह कालेधन का एक और पार्किंग स्थल रहा है। इससे कालेधन को समाप्त करने की सरकार की ईमानदारी प्रगट होती है।

नए बजट से आम आदमी को खर्च करने के लिए और अधिक धन उपलब्ध हो सकेगा। इस दृष्टि से यह बजट उपभोक्ता अनुकूल है और विकासपरक है। इससे मांग बढ़ेगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी।

इस पर आश्चर्य होता है कि वार्षिक एक्सरसाइज पर इतना बड़ा 'हंगामा' क्यों हो रहा है, जिसका कार्यकाल केवल 12 महीने का होता है। कांग्रेस वित्त मंत्रियों ने दशकों से सामान्य रूप से बजटों को काम किया है, जिसमें जमीनी रूप से एक के बाद एक कई वर्षों तक घोषणाओं को दोहराया जाता रहा है। मोदी सरकार ने इस सभी को परिवर्तित किया है और बजट को एक अर्थ देते हुए राष्ट्रीय निर्माण का ब्ल्यूप्रिंट बनाया है। यह टारगेटेड, लक्ष्यबद्ध और नीतिगत, विश्वसनीय नीति है। वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत चौथा बजट एक बार फिर राजनीतिक विचारधारा का शानदार बजट है जिससे वास्तव में जमीनी ट्रांसफोर्मेशन दिखाई पड़ता है। ■

(लेखक भाजपा केन्द्रीय प्रशिक्षु समिति और प्रकाशन समिति के सदस्य हैं।)

विजय शंखनाद रैली, अलीगढ़ (उप्र)

'विकास की मेरी सीधी परिभाषा है - 'वि' से विद्युत, 'का' से कानून और 'स' से सड़क': नरेंद्र मोदी

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के निमित्त प्रचार जोरों पर हैं। चार फरवरी से आठ मार्च के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधान सभा चुनाव होने हैं। चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे। चुनाव प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह सहित अनेक पार्टी नेताओं ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर पांचों राज्यों में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 फरवरी को अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित विशाल विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया और राज्य की जनता से यूपी के विकास के लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता को विकास का मतलब समझाते हुए कहा कि विकास की मेरी सीधी परिभाषा है - 'वि' से विद्युत, 'का' से कानून और 'स' से सड़क, इन तीन मजबूत पिलर पर हम विकास की मजबूत इमारत बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यूपी से कहना चाहता हूं कि यूपी को 'SCAM' से मुक्त करना है, उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दंगे का कारोबार हो गया है, यह बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में सपा और बसपा - दोनों सरकारों में अपराध में प्रदेश को आगे ले जाने की स्पर्धा हो रही है, मायावती कहती हैं कि मैं साइकिल से आगे, साइकिल वाले कहते हैं मैं मायावती से आगे। उन्होंने कहा कि मायावती के कार्यकाल में तीन गंभीर गुनाहों में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन हुआ करता था, ये युवा मुख्यमंत्री आए और इन्होंने पांच गंभीर गुनाहों में उत्तर प्रदेश को देश में नंबर वन कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक दिन में लगभग 13 हत्याएं होती हैं, 24 रेप होते हैं, 21 रेप के प्रयास होते हैं, 33 अपहरण होते हैं, 21 दंगे होते हैं, 126 चोरी की घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी बातें हैं जो हिम्मत करके थाने तक पहुंचते हैं, जो थाने पहुंच ही नहीं पाते, उनकी बात ही अलग है। उन्होंने कहा कि यूपी में हत्या, लूट का फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि हमें अपहरण, जमीन पर कब्जे से यूपी को निकालना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर गरीबों की जमीन कब्जाने वाले जेल में होंगे।

अमरोहा और नोएडा (उप्र)

भ्रष्टाचार और गुंडाराज का पर्याय उप्र सरकार: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के अमरोहा और नोएडा में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से भ्रष्टाचार और गुंडाराज की पर्याय बन चुकी सपा सरकार को जड़ से उखाड़ कर भारतीय जनता पार्टी की दो-तिहाई बहुमत वाली सरकार बनाने की अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यूपी का यह चुनाव किसी मुख्यमंत्री अथवा विधायक को बदलने का चुनाव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि 15 साल से उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा सरकारों के क्रम ने राज्य को बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी कुछ कॉस्मेटिक डेवलपमेंट (केवल दिखावटी वाले दो-तीन काम) करके यूपी की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जबकि राज्य में न तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा है, न शुद्ध पीने का पानी है, न गावों में 24 घंटे बिजली है और न ही किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल पा रहा है, वहीं भाजपा शासित प्रदेश विकास की नित-नई कहानी लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में एक किमी नेशनल हाइवे के निर्माण में 18 करोड़ रुपये की लागत आती है, जबकि अखिलेश सरकार में एक किमी की लागत 31 करोड़ रुपये है, अखिलेश सरकार को जवाब देना चाहिए कि प्रति किलोमीटर 13 करोड़ रुपया किधर जाता है?

विजय शंखनाद रैली, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

'उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो यहां की सरकार बदलिए'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 फरवरी को मेरठ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित विशाल विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया और राज्य की जनता से यूपी के विकास के लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रदेश से भ्रष्टाचारियों को भगाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सपा ने माफियाओं को टिकट दिए, दो महीने पहले जिनको उन्होंने खनन माफिया कहा, सपा को उन्हें टिकट क्यों देनी पड़ी, इनके इरादे नेक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज अपराध एवं भ्रष्टाचार के कारण उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रदेश से पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने जनता से पूछते हुए कहा कि आप ही बताइए कि क्या मोदी ने आज तक कोई भ्रष्टाचार किया है। क्या मोदी पर किसी ने भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगाया है, क्या मोदी ने देश का मस्तक नीचा करने वाला कोई भी काम किया है? (सभा में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा - नहीं)

श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर चीज़ को वोट बैंक से तौलती रही है, यहां गरीबों को सही से इलाज भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत यूपी की सपा सरकार को 7200 करोड़ दिए गए, लेकिन 400 करोड़ ही खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान के लिए प्रदेश सरकार को साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये दिए, ये चालीस करोड़ रुपये भी खर्च नहीं कर सके, ये परिवारवाद में ही उलझे रहे। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक है, इसे हटाना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो पहले यहां की सरकार बदलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जब तक आप उत्तर प्रदेश की सरकार को घर नहीं भेजते, तब तक मैं दिल्ली से आपके लिए जो भेजता हूं, वह आपके पास नहीं पहुंच सकता। कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि अभी ये कांग्रेस वाले गांव-गांव जाकर उत्तर प्रदेश को सपा सरकार द्वारा कैसे लूटा जा रहा है, बताया करते थे, आखिर रातों-रात ऐसा क्या हो गया कि आप उसके गले लग गए? उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जो सुबह शाम एक-दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे, आज एक दूसरे के गले लग गए। उन्होंने कहा कि जो पहले परिवार का सोचते थे, आज कुर्सी का सोचते हैं, ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश का भाग्य नहीं बदलेगा।

फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) रैली

'सपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकें'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आयोजित विशाल रैली को संबोधित किया और प्रदेश की जनता से राज्य की भ्रष्टाचारी सपा सरकार को जड़ से उखाड़ कर भारतीय जनता पार्टी की दो-तिहाई बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। भाजपा अध्यक्ष ने राज्य की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि आप मतदान किसी विधायक या मुख्यमंत्री को बदलने के लिए मत कीजिये, आप उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए वोट कीजिये। आपका वोट कई सालों तक उत्तर प्रदेश के युवाओं का भाग्य बदलने वाला है, बहन-बेटियों को सुरक्षा देने वाला है और प्रदेश के किसानों का कल्याण करने वाला है।

श्री शाह ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है तो सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के ऋण माफ़ कर दिए जायेंगे, उन्हें ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, राज्य से पलायन को रोकने की विशेष व्यवस्था बनाई जायेगी। छात्राओं को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जायेगी, वन जीबी कनेक्टिविटी के साथ बिना किसी भेदभाव के युवाओं को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा, 25 मेडिकल कॉलेज और 80 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जायेंगे ताकि युवाओं को पढ़ने के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े, साथ ही वर्ग तीन और चार की नौकरियों में से इंटरव्यू को भी ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर प्राथमिकी तुरंत दर्ज की जायेगी चाहे वह किसी भी धर्म व जाति का क्यों न हो, दोषियों की जवाबदेही तय किया जाएगा और जल्द इंसाफ की व्यवस्था की जायेगी।

मथुरा (उत्तर प्रदेश) रैली

'सपा सरकार को शासन में बने रहने का हक नहीं'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 फरवरी को मथुरा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित एक विशाल जन-सभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से यूपी के विकास के लिए प्रदेश की भ्रष्टाचारी अखिलेश सरकार को जड़ से उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक विचित्र प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा चल रही है। उन्होंने कहा कि हर राज्य देश में रोजगार, 24 घंटे बिजली, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में पहले नंबर पर काबिज होना चाहता है जबकि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने विकास की एक नई परिभाषा परिभाषित की है, वह हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाओं में पहले नंबर पर रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि हर रोज यूपी में दर्जनों हत्याएं और बलात्कार की घटना घटित हो रही है। उन्होंने राज्य की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि जो सरकार हत्या और बलात्कार जैसी निंदनीय घटनाओं को रोक नहीं सकती, उसे यूपी में शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। मथुरा को विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस मथुरा को भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है, भगवान् कृष्ण और मां यमुना की धरती के रूप में जाना जाता है, आज उसी मथुरा को लोग रामवृक्ष के नाम से जानने लगे हैं। ■

स्वच्छ और विकासशील प्रशासन भाजपा का लक्ष्य: अरुण जेटली

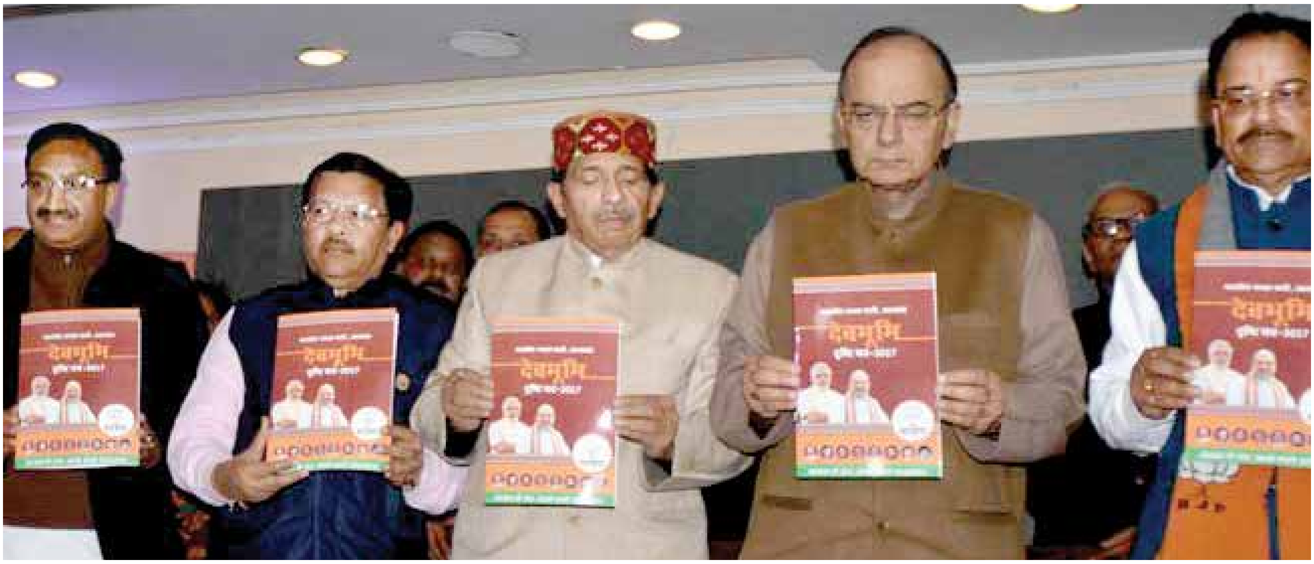

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 4 फरवरी को उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा-पत्र जारी किया। श्री जेटली ने उत्तराखंड और भाजपा के बीच विशेष संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का गठन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा के ही शासनकाल में हुआ था।

पार्टी के घोषणा-पत्र के बारे में श्री जेटली ने कहा कि काफी विचार-विमर्श के बाद इस घोषणा-पत्र को तैयार किया गया है और इसे तैयार करते हुए राज्य को स्वच्छ और विकासशील प्रशासन का लक्ष्य रखा गया है। श्री जेटली ने कहा कि एक पार्टी के तौर पर हम राज्य के चहुंमुखी विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्य की जनता भाजपा को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका देगी और राज्य को उसका वाजिब हक प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तेज गति से विकास के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए श्री जेटली ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता के चलते इस पर्वतीय प्रदेश का विकास बाधित हुआ है। श्री जेटली ने कहा कि हम आखिरी व्यक्ति तक शासन की पहुंच बनाना चाहते हैं। चूंकि उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, ऐसे में सुशासन विकास को तेज गति प्रदान कर सकता है। इसके अलावा श्री जेटली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी ने अलग राज्य की उम्मीद को पूरा किया, अब केंद्र की मोदी सरकार इसे खुशहाल बनाने के लिए संकल्प ले रही है। ■

घोषणा पत्र की मुख्य बातें

- भाजपा ने विजन डाक्यूमेंट 2017 के रूप में अपना घोषणा पत्र जारी किया।
- घोषणा पत्र में युवा, रोजगार, पलायन जैसे अहम मुद्दों को प्रमुखता दी गई है।
- भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सौ दिन में खंडूड़ी का लोकायुक्त एक्ट लागू होगा।
- साल 2019 तक हर गांव में सड़क होगी।
- मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
- सेवारत अतिथि व संविदा शिक्षकों व कर्मचारियों को भी उचित वेतन और पेंशन की व्यवस्था होगी।
- 24 घंटे बिजली-पानी की सप्लाई होगी।
- घोषणा पत्र में गया है कि है कि अगर भाजपा की सरकार आई तो रिक्त पदों पर 6 माह में भर्तियां हो जाएंगी।
- विवि को फ्री वाई-फाई की सुविधा।
- गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही रीजन में अस्पताल और हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे।
- गरीबी रेखा से नीचे जी रहे लोगों के विशेष हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाएंगे।
- किसानों को आर्गेनिक खेती के लिए खास तौर पर लोन दिए जाएंगे।
- मोदी सरकार द्वारा उत्तराखंड को खुशहाल बनाने का संकल्प।

आज ही लीजिए

कमल संदेश

की सदस्यता

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

और

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)................................ (2)................................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :.................................. दिनांक :............................ बैंक : ....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुबह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

मेरठ (उ.प्र.)

हरिद्वार (उत्तराखंड)

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में अबु धाबी के राजकुमार शेख मोहम्मद बिन जायद अल निहान से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रेषण तिथिः (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघरः लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने कमल संदेश के आजीवन सदस्य

कमल संदेश की कैशलेस सदस्यता लें!

आह्वान

आपको जानकर हर्ष होगा कि 6 दिसम्बर 2016 को पार्टी मुख्यालय में भाजपा 'कमल संदेश' का आजीवन सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. **श्री अमित शाह** ने पत्रिका की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 'कमल संदेश' भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय पत्रिका है और यह पाक्षिक रूप में हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है।

हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं 5000/– रुपए का चैक देकर 'कमल संदेश' की आजीवन सदस्यता ली। साथ ही केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री श्री मनोहर परिकर, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर सहित अनेक केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आजीवन सदस्यता ग्रहण की गई है।

'कमल संदेश' हिन्दी एवं अंग्रेजी के दोनों अंकों को 5000/– (पांच हजार रुपये) की सदस्यता शुल्क देकर नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब 'कमल संदेश' के लिए कैशलेस भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है। कृपया 5000/– (पांच हजार) रुपये का योगदान कर आप भी 'कमल संदेश' (हिन्दी+अंग्रेजी) का आजीवन सदस्य बनें।

एक साल (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹350/-	**तीन साल** (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹1000/-
आजीवन (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹3000/-	**आजीवन** (हिन्दी+अंग्रेजी)	—	₹5000/-

'कमल संदेश' के हमारे पाठकों से अनुरोध है कि इसकी सदस्यता लेकर जीवंत वैचारिक आंदोलन के भागीदार बनें।

कैशलेस बना 'कमल संदेश'

सदस्य बनें और बनाएं

☞ **www.kamalsandesh.org, www.bjp.org** पर जाकर कैशलेस भुगतान क्रेडिट/डेबिट/नेटबैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।

☞ साथ ही दिए बार कोड से मोबाइल द्वारा सीधा भुगतान भी कर सकते हैं।

chillr
ACCEPTED HERE
Scan the QR code to make a payment
Click on SCAN & PAY and enter amount
Add this contact to pay
+91 9911026172

"**कमल संदेश**" के नाम से कृपया चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
कमल संदेश, पीपी–66, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली– 110003